RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 082
दि. 24.12.2025,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

अटल नेतृत्व, अविरत विकास

मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना के जरिये राज्य के 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों को मिल रहा है शिक्षा के साथ पोषण

▸▸ गुजरात सरकार की संवेदनशील योजना बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है : अहमदपुर प्राथमिक शालाचार्य

▸▸ योजना अंतर्गत बच्चों को दिया जाता है सुखडी, चना चाट, मिक्स दलहन, मिलेट का अल्पाहार

▸▸ मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना द्वारा प्रधानमंत्री के 'पढ़ाई भी, पोषण भी' के ध्येय को साकार कर रही है गुजरात सरकार

(जीएनएस)। गांधीनगर : देश में सुशासन के मूल्यों को प्रोत्साहन देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री तथा भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती यानी 25 दिसंबर को 'सुशासन दिवस' के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने सुशासन के मूल्यों का अनुकरण करते हुए नागरिकों के सर्वांगीण कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की है। इनमें एक महत्वपूर्ण योजना है : मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना, जो बच्चों की शिक्षा के साथ उनका पोषण भी सुनिश्चित करती है। इस योजना का लाभ गुजरात के 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों को मिल रहा है। बच्चों की शिक्षा के साथ उनके पोषण पर भी बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन के अलावा; मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना अंतर्गत ताजा एवं पौष्टिक नाश्ता दिया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप सरकारी स्कूलों के प्रति बच्चों का लगाव बढ़ा है और साथ ही बच्चों में पोषण के स्तर में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त; सरकारी स्कूलों में आधुनिक क्लासरूम, पानी, बिजली, शौचालय, स्वच्छता, ट्रांसपोर्टेशन सहित सुविधाएँ उपलब्ध कराने में कोई कमी न रह जाए; इसके लिए राज्य सरकार सदैव कटिबद्ध है।"

मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना ने सुशासन को दी नई दिशा

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अपने 3 वर्ष के कार्यकाल के दौरान सुशासन, सेवा एवं विकास के नए मानदंड स्थापित किए हैं। उन्होंने लोक कल्याणकारी योजनाओं द्वारा राज्य की जनता का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर सुशासन को नई दिशा दी है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने 11 दिसंबर, 2024 को 'मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना' की शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सुपोषित गुजरात मिशन अंतर्गत सरकारी एवं अनुदानित प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को पीएम पोषण योजना के तहत दिए जाने वाले दोपहर के भोजन के अलावा पौष्टिक अल्पाहार भी मिले।

मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना : 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों को मिल रहा है कैलोरी-प्रोटीनयुक्त अल्पाहार

पीएम पोषण योजनांतर्गत समाविष्ट सभी स्कूलों में उपस्थित रहने वाले विद्यार्थी 'मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना' अंतर्गत नियमित लाभ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना अंतर्गत विद्यार्थियों को औसत 200 किलो कैलोरी तथा 6 ग्राम प्रोटीन से युक्त पौष्टिक अल्पाहार दिया जाता है। हाल में राज्य के लगभग 32,265 प्राथमिक विद्यालयों के 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों को कैलोरी-प्रोटीनयुक्त अल्पाहार मिल रहा है।

विद्यार्थियों की स्कूल में उपस्थिति से लेकर उनके पोषण के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई

गांधीनगर की देहगाम तहसील की अहमदपुर प्राथमिक शाला में विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना का लाभ मिल रहा है। यह योजना किस प्रकार बच्चों के लिए लाभदायी सिद्ध हुई है; इस संबंध में शाला के आचार्य श्री हसमुखभाई पटेल ने कहा, "मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना शुरू होने के बाद विद्यार्थियों की स्कूल में उपस्थिति से लेकर उनके पोषण के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में माता-पिता रोजमर्रा के कामों के लिए घर से बाहर जाया करते हैं। ऐसे में बच्चों को भोजन किए बिना स्कूल में आना पड़ता है। मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना शुरू होने से पहले स्थिति ऐसी थी कि कई बच्चे नियमित स्कूल नहीं आते और उनका पढ़ने में भी मन नहीं लगता। यह योजना शुरू होने के बाद विद्यार्थी नियमित स्कूल आने लगे हैं। इतना ही नहीं; इस योजना के कारण कुपोषित बच्चों की संख्या में भी उल्लेखनीय कमी आई है। विद्यार्थियों को अल्पाहार में दलहन (कठोळ) दिया जाता है, जिसके कारण उनका शारीरिक विकास भी हो रहा है। गुजरात सरकार की यह संवेदनशील योजना बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।"

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'पढ़ाई भी, पोषण भी' के ध्येय को साकार कर रही है गुजरात सरकार

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना अंतर्गत बच्चों को सुखडी (आटा-घी और गुड़-चीनी से बनने वाला खाद्यान्न), चना चाट, मिक्स दलहन, मिलेट का अल्पाहार दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना के लिए 617.67 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। गुजरात पीएम पोषण योजना अंतर्गत भोजन के अलावा; बालवाटिका से कक्षा 8 तक के सभी विद्यार्थियों को अल्पाहार देने का निर्णय लेने वाला अग्रिम राज्य है। गुजरात सरकार इस पोषणोन्मुखी योजना के क्रियान्वयन द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'पढ़ाई भी, पोषण भी' के ध्येय को साकार कर रही है।

पटना में शक्ति प्रदर्शन के साथ नितिन नबीन का भव्य स्वागत, बोले केरल से बंगाल तक फहराएगा भगवा, बिहार बनेगा विकास का मॉडल

(जीएनएस)। पटना। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बिहार पहुंचे नितिन नबीन का पटना में ऐसा भव्य स्वागत हुआ, जिसने सियासी माहौल को पूरी तरह गर्म कर दिया। एयरपोर्ट से लेकर मिलर स्कूल ग्राउंड तक निकले करीब छह किलोमीटर लंबे रोड शो ने इसे केवल स्वागत कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक बड़े शक्ति प्रदर्शन का रूप दे दिया। हाथी, घोड़े और ऊंट के साथ निकले इस रोड शो में हजारों कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। जगह-जगह फूलों की बारिश, ढोल-नगाड़ों की गूंज और 'जय श्री राम' के नारों से पूरा इलाका भगवामय नजर आया। बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी ने इस आयोजन को और भी खास बना दिया।

मिलर स्कूल ग्राउंड पहुंचने पर आयोजित अभिनंदन समारोह में नितिन नबीन ने अपने संबोधन में साफ शब्दों में पार्टी का आक्रामक राजनीतिक एजेंडा रखा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में केरल से लेकर पश्चिम बंगाल तक भगवा लहराएगा और भाजपा पूरे देश में अपनी वैचारिक और संगठनात्मक ताकत के दम पर आगे बढ़ेगी। उन्होंने बिहार को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि 2025 से 2030 तक का दौर बिहार के लिए ऐतिहासिक होगा, जब राज्य विकास के नए कीर्तिमान गढ़ेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस दौरान युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। अपने भाषण में नितिन नबीन ने कांग्रेस और विपक्ष पर तीखा हमला बोलने से भी परहेज नहीं किया। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि देश की जनता उन्हें उनकी राजनीति की सजा देगी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने राहुल गांधी को इस तरह नकारा कि वे जर्मनी चले गए। नितिन नबीन ने इसे 'पार्ट टाइम राजनीति' करार देते हुए कहा कि चुनाव हारने के बाद विदेश जाकर देश के खिलाफ बयान देना जनता सब देख रही है और समय आने पर जवाब भी देगी। इस दौरान उन्होंने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी निशाने पर लिया। नितिन नबीन ने कहा कि अब राजनीति में केवल परिवारवाद और खोखले वादों का समय खत्म हो चुका है। जनता जमीन से जुड़े, स्पष्ट सोच वाले नेतृत्व को ही स्वीकार करेगी और ऐसे लोगों को समय आने पर करारा जवाब देगी। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति अब निर्णायक मोड़ पर है और भाजपा इसे विकास और सुशासन की नई दिशा देने के लिए पूरी तरह तैयार है। नितिन नबीन ने अपने संबोधन में संगठनात्मक मजबूती पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक परचम लहराना है। इसके लिए पंचायत चुनाव से ही कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत, अनुशासन और समर्पण के साथ जुटना होगा। उन्होंने दोहराया कि बिहार को विकसित राज्य बनाने का संकल्प केवल नारा नहीं, बल्कि एक मिशन है, जिसे पार्टी हर स्तर पर लागू करेगी।

हिंसा और विद्रोह की आग में झुलसता बलोचिस्तान 2025 में सैकड़ों जानें गईं, शांति की उम्मीदें धुंधली

(जीएनएस)। क्वेटा। पाकिस्तान का अशांत प्रांत बलोचिस्तान वर्ष 2025 में भी लगातार हिंसा, विद्रोह और असुरक्षा के साये में रहा। आज़ादी की मांग को लेकर चल रहे लंबे संघर्ष और जवाबी सैन्य अभियानों के बीच यह साल बलोचिस्तान के सबसे खूनी वर्षों में दर्ज किया जा रहा है। विभिन्न हमलों, बम धमाकों और हथियारबंद घटनाओं में वर्ष 2025 के दौरान कम से कम 248 आम नागरिकों और 205 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई, जिससे पूरे प्रांत में भय और अस्थिरता का माहौल और गहरा गया।

द बलोचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट और उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्षभर में बलोचिस्तान में कुल 432 हिंसक घटनाएं दर्ज की गईं। इन घटनाओं ने न केवल सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए, बल्कि आम नागरिकों के दैनिक जीवन को भी बुरी तरह प्रभावित किया। बाजार, सड़कें, बसें और यहां तक कि धार्मिक व सरकारी प्रतिष्ठान भी हमलों की जद में रहे, जिससे आम लोगों में लगातार डर और असुरक्षा बनी रही।

2025 के दौरान प्रांत में आत्मघाती हमलों और बड़े आतंकी हमलों की एक श्रृंखला देखने को मिली। क्वेटा, मस्तुंग, खुजदार, तुरबत और नोकुंडी जैसे इलाकों में कुल छह आत्मघाती बम धमाके हुए, जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। 11 मार्च को बोलन इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया गया, जिसने पूरे देश का ध्यान बलोचिस्तान की ओर खींचा। 18 फरवरी को बरखान में हुई हिंसक घटना में सात लोगों की जान चली गई। 15 मई को खुजदार में एक बस को निशाना बनाए जाने से छह यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 30 सितंबर को क्वेटा स्थित फ्रंटियर कॉर्प्स मुख्यालय पर हुए आत्मघाती हमले में 12 लोगों की जान गई। इन घटनाओं ने यह साफ कर दिया कि विद्रोही समूह अब भी बड़े और संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाने की क्षमता रखते हैं।

पाकिस्तानी अधिकारियों का दावा है कि हालात पर काबू पाने के लिए वर्ष 2025 में बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए गए। आधिकारिक बयान के मुताबिक, पूरे प्रांत में 78,000 से अधिक खुफिया आधारित ऑपरेशन किए गए, जिनमें बलोच सशस्त्र समूहों के 707 सदस्यों के मारे जाने का दावा किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि ये अभियान बलोचिस्तान में शांति बहाल करने के उद्देश्य से लगातार जारी हैं और भविष्य में भी इनकी तीव्रता कम नहीं की जाएगी।

हालांकि, जमीनी हकीकत को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। आलोचकों और मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि बलोचिस्तान में होने वाली कई हिंसक घटनाएं रिपोर्ट ही नहीं की जातीं और सुरक्षाकर्मियों व नागरिकों के हताहतों की वास्तविक संख्या आधिकारिक आंकड़ों से कहीं अधिक हो सकती है। उनका कहना है कि केवल सैन्य कार्रवाई से समस्या का समाधान संभव नहीं है और इससे हालात और जटिल होते जा रहे हैं।

खैबर पख्तूनख्वा में फिर दहशत, पुलिस वैन पर घातक हमला, पांच कांस्टेबल शहीद

(जीएनएस)। इस्लामाबाद। पाकिस्तान के अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर आतंक की खूनी वारदात ने सुरक्षा हालात की गंभीर तस्वीर पेश कर दी है। करक जिले के गुरगुरी इलाके में सोमवार को अज्ञात हमलावरों ने पुलिस की एक वैन पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें पांच पुलिस कांस्टेबलों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हमला उस वक्त हुआ जब पुलिसकर्मी नियमित गश्त पर निकले थे। अचानक हुई गोलीबारी से इलाके में अफरातफरी मच गई और पूरे प्रांत में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गईं।

जिला पुलिस अधीक्षक शौकत खान ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि हमले में वैन सवार सभी पांच कांस्टेबल शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि हमला बेहद सुनियोजित तरीके से किया गया और हमलावर पहले से घात लगाए बैठे थे। घटना के तुरंत बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और पुलिस व अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमलावरों की तलाश के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं और संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। डान अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, शहीद पुलिसकर्मियों की पहचान कांस्टेबल शाहिद इकबाल, समीउल्लाह, आरिफ, सफदर और मोहम्मद अबरार के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी कांस्टेबल रोजमर्रा की ड्यूटी के तहत इलाके में गश्त कर रहे थे, तभी आतंकियों ने अचानक उनकी वैन को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमले की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला।

यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब खैबर पख्तूनख्वा पहले ही बढ़ती आतंकी घटनाओं से जूझ रहा है। दुनिया न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2025 में अब तक इस प्रांत में हुए आतंकी हमलों में सुरक्षा बलों और नागरिकों समेत कुल 502 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी अवधि में प्रांत भर में 1,588 आतंकी घटनाएं दर्ज की गई हैं, जो हालात की भयावहता को दर्शाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, इन हमलों में 223 आम नागरिकों की जान गई है और 570 लोग घायल हुए हैं। वहीं पुलिस बल को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब तक 137 पुलिस अधिकारी शहीद हुए हैं और 236 घायल हुए हैं। इसके अलावा अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के 18 कर्मियों ने भी अपनी जान गंवाई है, जिससे सुरक्षा बलों पर लगातार बढ़ते खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि फेडरल कांस्टेबुलरी को भी भारी क्षति पहुंची है। आतंकी घटनाओं में फेडरल कांस्टेबुलरी के 124 जवान शहीद हुए हैं और 244 घायल हुए हैं। इसके जवाब में सुरक्षा बलों ने कई बड़े अभियान चलाने का दावा किया है, जिनमें 348 आतंकवादियों को मार गिराने की बात कही गई है। हालांकि, इसके बावजूद हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।

आंकड़ों के अनुसार, आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में बन्नू जिला सबसे ऊपर है, जहां 394 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इस क्षेत्र में 41 पुलिस अधिकारी शहीद हुए और 89 घायल हुए, जबकि 54 नागरिकों की मौत और 125 के घायल होने की पुष्टि हुई है। इसके अलावा डेरा इस्माइल खान, उत्तरी वजीरिस्तान और दक्षिणी वजीरिस्तान जैसे इलाकों में भी हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। उत्तरी वजीरिस्तान में 181 मामलों में 38 नागरिकों की मौत और 182 लोगों के घायल होने की सूचना है, जबकि दक्षिणी वजीरिस्तान में 103 घटनाओं में 39 नागरिक मारे गए और 86 घायल हुए हैं।

बांग्लादेश में हिंदू युवक की नृशंस हत्या पर देशभर में आक्रोश, दिल्ली और कोलकाता की सड़कों पर उबाल

(जीएनएस)। नई दिल्ली/कोलकाता। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की नृशंस मॉब लिंचिंग की घटना ने भारत में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है। इस जघन्य हत्या के विरोध में मंगलवार को दिल्ली और कोलकाता में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित कई हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किए। राजधानी दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सड़कों पर गुस्से का सैलाब दिखाई दिया। कहीं बांग्लादेशी हाई कमीशन के घेराव की कोशिश हुई तो कहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से जुड़े चेहरों के पुतले फूंके गए। कई जगह प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव और झड़प की स्थिति भी बनी। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के आसपास हालात सबसे ज्यादा तनावपूर्ण नजर आए। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी भगवा झंडे, बैनर और तख्तियां लेकर हाई कमीशन की ओर बढ़े। उन्होंने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू करनी पड़ी। करीब 15 हजार पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई और तीन स्तर के बैरिकेड लगाए गए। प्रदर्शनकारियों को हाई कमीशन से लगभग 800 मीटर पहले ही रोक दिया गया। स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए DTC की बसों को भी अवरोधक के तौर पर खड़ा किया गया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में मौजूद पोस्टरों पर "हिंदू रक्त की एक-एक बूंद का हिसाब चाहिए" जैसे नारे लिखे हुए थे, जो गुस्से और पीड़ा को साफ तौर पर दर्शा रहे थे।

प्रदर्शन की जड़ में 18 दिसंबर को बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले के बालुका इलाके में हुई वह दिल दहला देने वाली घटना है, जिसमें 25 वर्षीय परिधान फैक्ट्री मजदूर दीपू चंद्र दास को कथित तौर पर ईशनिंदा के आरोप में भीड़ ने बेरहमी से पीटा, फिर पेड़ से लटका दिया और बाद में उसके शव को जला दिया गया। इस घटना की तस्वीरें और वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुए, तो भारत समेत कई देशों में आक्रोश फैल गया। भारत में खासतौर पर हिंदू संगठनों ने इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा का प्रतीक बताते हुए कड़ा विरोध शुरू कर दिया।

कोलकाता में भी हालात कम उग्र नहीं रहे। बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बेकरबागान इलाके में रोक दिया। जब प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने लगे, तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान अफरातफरी मच गई और कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। पुलिस ने कम से कम 12 लोगों को हिरासत में लिया। प्रदर्शन के दौरान "हिंदू हिंदू भाई-भाई" और "बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा करो" जैसे नारे गूंजते रहे, जिससे माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। प्रदर्शनकारियों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप लगाया कि पुलिस हिंदू संगठनों के खिलाफ सख्ती दिखा रही है, जबकि मूल मुद्दे को नजरअंदाज किया जा रहा है। विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने चेतावनी दी कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुके, तो 26 दिसंबर को इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से कहा गया कि इस संवेदनशील मुद्दे को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए और शांति बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। उधर, बांग्लादेश में भी दीपू चंद्र दास की हत्या के खिलाफ विरोध के स्वर उठ रहे हैं। वहां शांति मार्च और मानव श्रृंखला के जरिए लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, हालांकि डर और असुरक्षा का माहौल अब भी बना हुआ है। भारत में हुए प्रदर्शनों के बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव भी बढ़ गया है। वीजा कार्यालयों को बंद किया गया है और एक-दूसरे के राजनयिकों को तलब किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

सौ झूठ बोलिए, कौआ नहीं काटेगा!

सौ झूठ बोलिए, कौआ नहीं काटेगा—यह पंक्ति आज के समय की सबसे सटीक कहावत बन चुकी है। कभी लोकगीतों में चेतावनी हुआ करती थी—'झूठ बोले कौआ काटे'—लेकिन लगता है वह चेतावनी किसी पुराने युग के लिए थी। आज के दौर में झूठ न सिर्फ बोला जाता है, बल्कि पूरे आत्मविश्वास, गर्व और रणनीति के साथ बोला जाता है। इतना ही नहीं, झूठ अब किसी अपराध की तरह नहीं, बल्कि एक कला, एक हथियार और कई बार तो सफलता की सीढ़ी बन चुका है।

यदि कौआ सचमुच झूठ पर काटता होता, तो कुछ 'महानुभाव' 993 दिनों में 13 हजार से ज्यादा झूठ बोलने का रिकॉर्ड कैसे बना पाते? यह आंकड़ा भी कोई अंतिम नहीं है, यह तो छह महीने पुराना बताया जाता है। उसके बाद झूठों की संख्या कितनी बढ़ी होगी, इसकी गणना करना भी मुश्किल है। हैरत की बात यह नहीं कि झूठ बोले जा रहे हैं, हैरत इस बात की है कि उन्हें न तो कोई काट रहा है, न कोई रोक रहा है। न कौआ, न कुत्ता, न जमीर।

'मैंने फलां-फलां युद्ध रुकवा दिया'—यह दावा अब इतना बार दोहराया जा चुका है कि खुद झूठ भी शरमा जाए। एक ऐसे तथाकथित युद्ध को लेकर 70 से ज्यादा बार बयान दिए गए, जो युद्ध था ही नहीं। वह तो एक देश द्वारा आतंक के खिलाफ चलाया गया सीमित सैन्य ऑपरेशन था। उस देश ने खुद इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन झूठ के पांव कहां रुकते हैं। वह चलता ही जाता है, बयान दर बयान, मंच दर मंच।

विडंबना तो यह है कि इन्हीं झूठों के सहारे शांति के नोबेल पुरस्कार तक की ख्वाहिश पाली गई। सदी का शायद सबसे बड़ा मजाक यही है कि असत्य के सहारे सत्य का सबसे बड़ा सम्मान पाने की लालसा रखी जाए। लेकिन आज के समय में मजाक और गंभीरता की रेखा भी कहां साफ बची है।

यह किसी एक व्यक्ति या एक देश की बात नहीं है। झूठ अब राजनीति की रीढ़ बन चुका है। बिना झूठ बोले नेता बनने की कल्पना आज उतनी ही असंभव है, जितनी बिना पानी के मछली। झूठे आंसू बहाना, भावुक भाषण देना, जनता को गुमराह करना—यह सब अब राजनीतिक प्रशिक्षण का हिस्सा लगता है। उनकी भावनाएं घड़ियाल के आंसुओं जैसी हैं—बाहर से करुणा, भीतर से रणनीति।

धीरे-धीरे यह मानसिकता बन चुकी है कि झूठ बोलने में डरने की जरूरत नहीं। कोई कौआ नहीं काटेगा। जब दिन-रात झूठ बोलने वाले विश्व रिकॉर्ड बना रहे हों और सम्मान पा रहे हों, तो आम आदमी एकाध झूठ बोल ले, इसमें डरने जैसा क्या है? यही सोच समाज के हर कोने में फैलती जा रही है।

आज झूठ के बिना गुजारा किसका है? कानून के रखवाले को ही देख लीजिए। उन्हें अपने पक्षकार को जिताना होता है, तो सच के साथ झूठ का सहारा लेना पड़ता है। इसे 'पेशेगत मजबूरी' कहा जाता है। हम समझ लेते हैं, लेकिन क्या कौआ भी यह मजबूरी समझता है? या वह भी अब व्यवस्था का हिस्सा बन चुका है?

यह मत कहिएगा कि काला कौआ वकीलों के काले कोट से डरता है। अगर ऐसा होता तो चिकित्सक तो सफेद कोट पहनते हैं। क्या वे राजा हरिश्चंद्र की परंपरा से आते हैं? कितनी बार ऐसा होता है कि डॉक्टर जानते हैं—अब कुछ बचा नहीं है, ऊपर से टिकट कन्फर्म हो चुका है—फिर भी परिजनों से कहते हैं, "कोशिश जारी है, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा।" यह झूठ नहीं तो और क्या है? शायद यह भी 'पेशेगत करुणा' के नाम पर स्वीकार्य बना दिया गया है।

वैसे झूठ कौन नहीं बोलता? किस-किस की गिनती की जाए? नेता, अफसर, व्यापारी, पेशेवर, समाजसेवी—हर किसी के झूठ का अपना रंग, अपना तरीका है। कोई आंकड़ों में झूठ बोलता है, कोई भावनाओं में, कोई चुप्पी के जरिए, तो कोई आधे सच के सहारे पूरा झूठ परोस देता है।

आज झूठ खुद चीख-चीख कर कह रहा है—"इस ज़मीं से आसमां तक मैं ही मैं हूं।" सच को अब सफाई देनी पड़ती है, प्रमाण जुटाने पड़ते हैं, जबकि झूठ बिना सबूत के भी वायरल हो जाता है। झूठ तेज है, आकर्षक है, सुविधाजनक है।

कौआ अब किसी को काटता नहीं दिखता। शायद वह भी समझ चुका है कि इस दुनिया में झूठ अकेला नहीं है, पूरा तंत्र उसके साथ खड़ा है। इसलिए अंत में बस यही कहा जा सकता है—जो सच है, वही आपको बता दिया गया, क्योंकि आखिर में इतना तो हम कह ही सकते हैं—"मैं झूठ नहीं बोलता।"

अटूट महराब पंजाब की स्थापना के 60 साल

> पंजाब भारत गणराज्य का पहरुआ है, सहज प्रवृत्ति से। पुनर्गठन के साठ साल बाद, यह राज्य फिर से इतिहास की दहलीज पर खड़ा है। यह एक ऐसा समाज है जो कठिनाई को हास्य में और बलिदान को गर्व में बदल देता हो, इतना सहनशक्ति युक्त जिसको कोई संकट तोड़ नहीं सकता।

मजबूती कभी भी संयोगवश नहीं मिलती; बल्कि यह एक विरासत है। हरेक सभ्यता के चरित्र की परीक्षा सरहद पर जाकर होती है, और भारत की आत्मा के लिए, वह सरहद हमेशा पंजाब रही है। गुरु नानक की शांत सार्वभौमिकता से लेकर भगत सिंह की ललकार तक, पंजाब ने सिर्फ़ एक सीमा की रक्षा नहीं की है; इसने गणतंत्र की चेतना को आकार भी दिया। चंद इलाकों की यादों में इतना दुख, सेवाभाव, और सहज वृत्ति भरा आलोक होगा। पुनर्गठन के साठ साल बाद, पंजाब फिर से इतिहास की दहलीज पर खड़ा है। विभाजन ने परिवारों, खेतों व आस्था को बांट दिया था, फिर भी पंजाब टूटा नहीं। इसने भस्म हुई भूमि से अपनी उपजाऊ मिट्टी का पुनर्निर्माण किया और एक भूख से जूझते राष्ट्र का पेट भरा। जब 1966 में नई सीमा रेखाएं खींची गईं, तब पंजाब ने शांति के साथ उन्हें भी जज़्ब किया, जो जानते हैं कि भूगोल बदल सकता है, लेकिन चरित्र नहीं। जब 1980 के दशक में उग्रवाद का अंधेरा छाया, तो जहां इसके किसान बेटे ने थकी हुई ज़मीन से जीवन निकाला तो वहीं सैनिक पुत्र ने मोर्चा संभाले रखा। पंजाब ने शोर-शराबे से नहीं, बल्कि निष्ठापूर्वक सहन किया। ये यादें आधार का मूल ढांचा बनाती हैं, वह गहरी अनदेखी किरण जिसने गणतंत्र को बार-बार तूफानों में स्थिर रखा। एक ऐसा समाज जो कठिनाई को हास्य में और बलिदान को गर्व में बदल देता हो, इतनी सहनशक्ति युक्त जिसको कोई संकट तोड़ नहीं सकता। जब कभी परीक्षा की घड़ी आई, तो पंजाब की प्रवृत्ति पीछे हटने की नहीं रही, बल्कि खुद को स्थिर करते हुए राष्ट्र को भी स्थिरता दी।

सहनशक्ति की संपूर्ण कीमत : तथापि,सहनशक्ति की भी गंभीर कीमत होती है। बार-बार सरहद पर खड़े रहने का मतलब है तनाव के कहीं और फूट पड़ने से पहले ही उसे जज़्ब कर लेना। थकावट खुद को असफलता के रूप में घोषित नहीं करती; बल्कि यह घटता मुनाफा, टलता नवीनीकरण, और इस मौन अनुमान से है कि सहनशक्ति अनिश्चित काल तक खुद-ब-खुद भरपाई करती रहेगी। उपजाऊ मिट्टी का ह्रास, सीमित विकल्प और एक पीढ़ी जो तेज़ी से

विदेशों की ओर खिंची चली जा रही है, इन सबके बीच पंजाब यह कीमत बिना किसी शिकायत के सहता आया है। मामला हमदर्दी का नहीं, यथार्थवाद का है। नवीनीकरण तब ज़रूरी नहीं होता जब पतन आसन्न हो, बल्कि जब धीरज बहुत ज़्यादा खिंच चुका हो।

बयानबाजी से सुधार की ओर : अनुशासन के बिना आशावाद भ्रम बन जाता है। पंजाब सिर्फ़ भावनाओं के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकता। नवीनीकरण संरचनात्मक होना चाहिए, न कि घटनाओं से जुड़ा, ज़िम्मेदारी पर आधारित, न कि शिकायत पर।

पंजाब का नवीनीकरण विभाजन द्वारा निर्मित बाधाओं के बोझ तले हो रहा है। यह कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है जिसकी समुद्र तट तक पहुंच नहीं। इसकी मिट्टी दशकों से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का बोझ उठाए है। इसकी प्रहरी ज़िम्मेदारियां बढ़ रही हैं, जो अब नशीले पदार्थों, ड्रोन और सीमा पार के आपराधिक नेटवर्क से और जटिल हो गयीं। ये इच्छाशक्ति की कमी नहीं, भूगोल और ज़िम्मेदारी की सच्चाई हैं।

किसी भी क्षेत्र को सिर्फ़ ढांचागत रूप से इस आधार पर नुकसान नहीं होना चाहिए कि वह वहां है जहां इतिहास ने उसे रख दिया। मदद, राष्ट्रीय सेवा की भरपाई के रूप में, आवश्यक रूप से नवीनीकरण मज़बूत करने वाली हो, न कि राजकीय खैरात की ओर धकेलने वाली। एक प्रहरी राज्य की सततता तमाशेबाजी से नहीं, संरक्षता निभाने पर टिकी होती है। पंजाब का इतिहास एक और गंभीर सबक देता है। इसे शायद ही कभी अपने पल चुनने की विलासिता मिली हो; इसकी बजाय इतिहास इसे चुनता आया है। हर पीढ़ी को विरासत में खाली पन्ना नहीं, बल्कि ज़िम्मेदारियों भरा खाता मिलता है, कुछ दिखाई देने वाली, कुछ अलिखित उसमें शामिल। जो लचीलापन प्रतीत होता है, वह निरंतरता है : खेत संभाले जाते हैं क्योंकि ऐसा करना ज़रूरी है, सीमाओं की रक्षा की जाती है क्योंकि किसी को वहां पहरे पर खड़ा होना है, संस्थानों को जारी रखा जाता है क्योंकि छोड़ देने पर मरम्मत खर्च ज्यादा आएगा। इस विरासत ने एक ऐसे स्वभाव को आकार दिया जो दिखावे के बजाय स्थिरता को, और टूटन की बजाय नवीनीकरण को महत्व देता है। अब काम पंजाब को फिर से बनाना नहीं, बल्कि सुनिश्चित करना है कि जो कुछ पीढ़ियों से चला आ रहा, वह लापरवाही से खत्म न होने पाए। आखिर, निरंतरता सिर्फ़ यादों से संरक्षित नहीं रहती; यह समय पर नवीनीकरण से बनी रहती है।

भीतरी नवीनीकरण के पांच स्तंभ :

1.पारिस्थितिक समझौता : पंजाब की कृषि सफलता एक समय देश के लिए एक बचाव बना। आज, नवीनीकरण को ज़मीन के साथ एक नये समझौते की ज़रूरत है। भविष्य बिना भरपाई वाला दोहन करने में नहीं, बल्कि संतुलन बनाने में है, मिट्टी की उर्वरता की पुनः बहाली, जल संचयन और पारिस्थितिकी संभाल को लागत की बजाय विरासत मानने में है। भूरी क्रांति (मृदा स्वास्थ्य बहाली और कृषि अवशेष प्रबंधन में सुधार) एक पारिस्थितिक समझौता है: मिट्टी को कारखाने के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवित विरासत मानने का संकल्प। अपनी ज़मीन का कार्बन संतुलन और इसकी प्रवृत्ति को बहाल कर, हम यकीनी बना सकते हैं कि ट्यूबवेल थमने के बहुत बाद भी पंजाब के खेत उपजाऊ रहें।

2.पलायन से आकांक्षा तक : कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता यदि हररोज उसकी उम्मीद (युवा) परदेस को पलायन करे। पंजाब को ऐसी जगह बनना होगा जहां आकांक्षा को विदेश ले जाने वाले पंखों की बजाय घर की जड़ें मिलें, जहां बसने के साथ ही स्वदेश की गरिमा, उद्देश्य व अवसर चुनने के रूप में देखा जाए। शिक्षा, कौशल और उद्यम को स्थानीय स्तर पर एक साथ आना होगा, ताकि भविष्य वहां बने जहां पहचान मज़बूत हो, न कि वहां जहां अपनापन न्यूनतम हो।

3.उद्योग बतौर स्थायित्व हो न कि विकल्प : पंजाब को कृषि को छोड़ने के लिए उद्योग नहीं चाहिए,बल्कि वह मूल्य संवर्धन से इसे मज़बूती देने वाला हो। मूल्य-संवर्धक उद्यम जैसे एग्रो-प्रोसेसिंग, कृषि संबंधी विनिर्माण, माल आवाजाही और सामग्री–जिसकी जड़ें ज़मीन और कौशल में हों, वह युवाओं, आत्मविश्वास और क्षमता को स्वदेश में बनाए रखेगी। प्रहरी राज्य में, उद्योग का अर्थ सिर्फ़ उत्पादन नहीं; जब घर, चूल्हा और उद्यम एक ही जगह हों, तो परिवार मज़बूत होते हैं, समाज को फ़ायदा होता है और सुरक्षा सुदृढ़ होती है।

4. पूर्व सैनिकों से मिलने वाला फायदा : सामग्री-संचालन, कृषि उत्पाद प्रसंस्करण, भूरी क्रांति, ड्रोन सेवाएं, साइबर सुरक्षा, शिक्षण, राष्ट्रमंडल एवं ओलंपिक प्रतियोगिताओं के लिए खेल तैयारी, और आपातकाल में प्रतिक्रिया बनाने में पूर्व सैनिकों द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप सैन्य क्षमता को नागरिक मूल्य में बदल देते हैं। पूंजी निवेश किसी सब्सिडी चालित आर्थिकी का नहीं आत्मविश्वास भरी अर्थव्यवस्था में होता है, और सेवानिवृत फौजी एक प्रहरी प्रांत की अर्थव्यवस्था में निर्णायक गुणक बन सकते हैं।

5.वैश्विक पंजाबी प्रवासी : अनिवासी भारतीय समुदाय दुनियाभर के बाजारों व संस्थानों में गहरे स्थापित है। गरिमा के साथ इन्हें जोड़ने पर,ये लोग पंजाब के नवीनीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं, महज विदेश से पैसा भेजने वाले के रूप में नहीं, बल्कि साझा उद्देश्य में भागीदार के तौर पर, जो पंजाबियत में है। पंजाबी अनिवासी खेल प्रतियोगिताओं से लेकर साहित्य समारोहों तक, सांस्कृतिक और नागरिक मंच बनाकर इस जुड़ाव को आत्मविश्वास में बदल सकते हैं। प्रवृत्ति खुद रोशनी बनने की हो।

छठा स्तंभ : प्रहरी राज्यों के लिए विचार : सीमावर्ती क्षेत्रों पर कुछ ऐसे बोझ होते हैं जिन्हें नीतियां अक्सर अनदेखा करती हैं। जब भूमि, बाजार व सतर्कता राष्ट्रहित में समर्पित हों, तो कीमत स्थायी होती है। इसलिए प्रहरी राज्यों हेतु विशेष विचार करना रियायत न होकर नीतिगत हो, यह संतुलन व निष्पक्षता का मामला है। जहां भूगोल स्थायी राष्ट्रीय कर्तव्य सौंपता हो, वहां स्थायी राष्ट्रीय लागत भी साथ आती है। जहां समानता की भागीदारी संस्थागत नीतियों में निहित हो जाए, तब सहनशक्ति थकान की बजाय आत्मविश्वास संग टिकाऊ बनी रहती है। जो गणराज्य अपने प्रहरियों को मान्यता देता है, वह स्थिरता को सुरक्षित करता है। महराब अटूट रहती है : सहनशक्ति, भले ही चरित्र में हो, असीमित नहीं होती। जो क्षेत्र सबसे लंबे समय तक मोर्चा संभाले रखते हैं, वे ऐसा अपने पारिस्थितिकी, सामाजिक और नैतिकता के भंडार इस्तेमाल करके करते हैं, जिन्हें अंततः नवीनीकृत करना पड़ता है। पंजाब ने कभी भी अपने कर्तव्य को पुरस्कार से नहीं मापा, न ही अपने जुड़ाव को मान्यता दिए जाने की चाहत से। यह जहां खड़ा है, वहां इसलिए है क्योंकि इतिहास ने इसे वहां रखा है... क्योंकि चरित्र ने इसे वहां रखा है। पंजाब भारत का पहरुआ है, सहज प्रवृत्ति से। यह केवल गणराज्य में भाग ही नहीं लेता; उसे लय भी प्रदान करता है। मिट्टी को ठीक किया जा सकता है, युवाओं को स्वदेश में रहने के लिए जोड़ा जा सकता है, और प्रहरी को और ऊपर उठने दिया जा सकता है। पंजाब पहले खुद को स्थिर करेगा और ऐसा करते हुए, गणराज्य को संवार देगा।

प्रेरणा

समर्पण की धारा में बहता जीवन

संत ज्ञानेश्वर का व्यक्तित्व ऐसा था, जो साधारण से साधारण दृश्य में भी जीवन का गहरा रहस्य खोज लेता था। उनका जीवन केवल ग्रंथों और श्लोकों तक सीमित नहीं था, बल्कि प्रकृति, समाज और मनुष्य के रोज़मर्रा के अनुभवों में ही वे ईश्वर का साक्षात्कार कर लेते थे। एक बार की बात है, संत ज्ञानेश्वर अपने शिष्यों के साथ यात्रा करते हुए एक हरे-भरे बाग के पास से गुजर रहे थे। चारों ओर फैली हरियाली, हवा में घुली मिट्टी की सौंधी खुशबू और पंक्तिबद्ध खड़े पौधों के बीच एक माली शांत भाव से पानी दे रहा था। सूरज की किरणें पानी की धाराओं पर पड़कर चमक रही थीं और हर पौधा मानो जीवन से भर रहा था।

इस दृश्य को देखकर संत ज्ञानेश्वर अचानक रुक गए। उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान फैल गई, जैसे उन्होंने किसी बड़े सत्य को पकड़ लिया हो। उन्होंने शिष्यों से पूछा कि क्या उन्होंने कभी ध्यान दिया है कि पानी वास्तव में क्या सिखाता है। शिष्य कुछ पल चुप रहे। किसी ने कहा कि पानी जीवन देता है, किसी ने उसकी शीतलता और शुद्धता की बात की। संत ज्ञानेश्वर ने सिर हिलाया और कहा कि ये सभी बातें सही हैं, लेकिन पानी का सबसे बड़ा गुण इससे कहीं अधिक गहरा है। पानी अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता। वह यह नहीं पूछता कि उसे कहां जाना है, किस पौधे को सींचना है या किस रास्ते से बहना है। माली जहां उसे ले जाता है, वह बिना विरोध वहीं चला जाता है।

संत ने समझाया कि यही समर्पण पानी को महान बनाता है। पानी न तो अपने अस्तित्व का ढिंढोरा पीटता है, न अपने अधिकारों की बात करता है। वह बस बहता है, देता है और फिर भी खाली नहीं होता। इसके विपरीत मनुष्य हर समय अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं और योजनाओं में उलझा रहता है। वह चाहता है कि जीवन उसकी शर्तों पर चले, लोग उसकी सोच के अनुसार व्यवहार करें और ईश्वर भी उसकी प्रार्थनाओं को तुरंत पूरा करे। जब ऐसा नहीं होता, तो मन में असंतोष, क्रोध और निराशा जन्म लेती है। मनुष्य भूल जाता है कि वह स्वयं सृष्टि का निर्माता नहीं, बल्कि उस विशाल योजना का एक छोटा सा हिस्सा है।

संत ज्ञानेश्वर ने शिष्यों से कहा कि ईश्वर को माली की तरह देखो। माली जानता है कि किस पौधे को कितना पानी चाहिए, किसे कम और किसे अधिक। अगर पानी स्वयं निर्णय लेने लगे कि वह किसे कितना मिलेगा, तो बाग नष्ट हो जाएगा। उसी तरह यदि मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि से यह तय करने लगे कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत, तो जीवन में अव्यवस्था फैल जाती है। ईश्वर की इच्छा हमारे अहंकार से कहीं व्यापक है। वह हमें उन रास्तों पर भी ले जाता है, जो हमें कठिन लगते हैं, लेकिन वही रास्ते हमारे भीतर की शक्ति और समझ को विकसित करते हैं।

उन्होंने कहा कि पानी की एक और विशेषता यह है कि वह कठोरता से नहीं, कोमलता से जीतता है। पत्थर के सामने पानी लड़ता नहीं, लेकिन निरंतर बहते रहने से वही पत्थर को घिस देता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हर समस्या का समाधान टकराव से नहीं होता। धैर्य, विनम्रता और निरंतरता से बड़ी से बड़ी बाधा भी मार्ग दे देती है। मनुष्य जब अहंकार छोड़कर परिस्थितियों के साथ बहना सीख लेता है, तब जीवन का संघर्ष भी साधना बन जाता है।

संत ज्ञानेश्वर ने यह भी स्पष्ट किया कि समर्पण का अर्थ पलायन या आलस्य नहीं है। पानी बहता है, सक्रिय रहता है, जीवन को संजीवनी देता है। उसी तरह मनुष्य को भी अपने कर्म पूरे मन से करने चाहिए। मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा से किया गया कर्म ही जीवन को अर्थ देता है। लेकिन कर्म के फल को लेकर जो चिंता, भय और लालसा है, उसे ईश्वर पर छोड़ देना ही सच्चा समर्पण है। जब फल की आसक्ति समाप्त हो जाती है, तब मन हल्का हो जाता है और कार्य अपने आप सुंदर रूप ले लेता है।

शिष्य यह सब सुनकर भीतर तक प्रभावित हो गए। उन्हें लगा कि जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान किसी बड़े उपदेश में नहीं, बल्कि इस सरल समझ में छिपा है कि स्वयं को ईश्वर की इच्छा में बहने देना है। जब मनुष्य पानी जैसा बन जाता है, तब दुख उसे कठोर नहीं बनाता और सुख उसे अहंकारी नहीं बनाता। वह हर स्थिति को स्वीकार करना सीख लेता है। संत ज्ञानेश्वर ने अंत में कहा कि जीवन में जब भी असमंजस हो, प्रकृति की ओर देखो। पानी, हवा, पेड़ और आकाश सब हमें यही सिखाते हैं कि समर्पण में ही शांति है। जो स्वयं को ईश्वर की धारा में छोड़ देता है, उसका जीवन बोझ नहीं रहता, बल्कि एक सहज यात्रा बन जाता है। यही समर्पण की धारा में बहता जीवन है, और यही मनुष्य को भीतर से मुक्त और पूर्ण बनाता है।

अमेरिकी दबाव के बीच भारत की नई व्यापारिक रणनीति, न्यूज़ीलैंड के साथ एफटीए से खुले अवसरों के द्वार

दुनिया की अर्थव्यवस्था इस समय एक बड़े भू-राजनीतिक और व्यापारिक उलटफेर के दौर से गुजर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक व्यापार नीतियों, ऊंचे टैरिफ और संरक्षणवाद की सोच ने वैश्विक व्यापार व्यवस्था को झकझोर दिया है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। वर्षों से अमेरिका भारत का एक प्रमुख निर्यात गंतव्य रहा है, लेकिन अब वहां से आने वाले संकेत स्पष्ट कर रहे हैं कि भविष्य में भारतीय उत्पादों के लिए रास्ता पहले जैसा सहज नहीं रहने वाला। ऐसे समय में भारत सरकार ने यह समझ लिया है कि केवल एक या दो बड़े बाजारों पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। इसी सोच के तहत भारत ने निर्यात विविधीकरण को प्राथमिकता दी है और अधिक से अधिक देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते करने की दिशा में तेज कदम बढ़ाए हैं।

इसी रणनीति की एक अहम कड़ी के रूप में भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सामने आया है। यह समझौता ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिकी टैरिफ विवाद के कारण वैश्विक व्यापार का माहौल नकारात्मक बना हुआ है। ऐसे में न्यूज़ीलैंड के साथ एफटीए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए न केवल राहत की खबर है, बल्कि यह भविष्य की दिशा भी तय करता है। यह समझौता यह संकेत देता है कि भारत अब वैश्विक व्यापार में अधिक आत्मविश्वास के साथ, बहुपक्षीय और संतुलित रिश्तों की ओर बढ़ रहा है।

इस समझौते के तहत न्यूज़ीलैंड ने भारत से आने वाले लगभग सभी उत्पादों को शून्य शुल्क पर अपने बाजार में प्रवेश देने का वादा किया है। इसका सीधा लाभ भारतीय निर्यातकों को मिलेगा, जिन्हें अब न्यूज़ीलैंड जैसे विकसित और स्थिर बाजार में प्रतिस्पर्धा का बेहतर अवसर मिलेगा। खासकर मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, टेक्सटाइल और आईटी सेवाओं से जुड़ी भारतीय कंपनियों के लिए यह एक नई जमीन तैयार करेगा। इसके साथ ही भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर डेयरी और कृषि से जुड़े उत्पादों को पूरी तरह सुरक्षित रखा है। दूध, दही, पनीर, चीनी, दालें और कुछ अन्य जरूरी उत्पादों पर कोई शुल्क रियायत नहीं दी गई है, ताकि भारतीय किसानों और छोटे व्यापारियों के हितों पर कोई आंच न आए। न्यूज़ीलैंड को इस समझौते से कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। वहां से आने वाले ऊन, लकड़ी, कोयला और भेड़ के मांस जैसे उत्पादों पर भारत ने शुल्क में छूट दी है। इसके अलावा कीवी, वाइन, चेरी, एवोकैडो और शहद जैसे उत्पादों को सीमित रियायतें दी गई हैं, लेकिन इन पर भी सख्त सुरक्षा प्रावधान लागू रहेंगे। इसका मकसद यह है कि भारतीय बाजार में अचानक सस्ते आयात से घरेलू किसानों को नुकसान न हो।

हालांकि, इस समझौते को लेकर न्यूज़ीलैंड के भीतर ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। वहां के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने इसे न तो पूरी तरह फ्री और न ही फेयर बताते हुए आलोचना की है। उनका कहना है कि इस एफटीए में न्यूज़ीलैंड को अपेक्षाकृत कम लाभ मिला है, खासकर डेयरी जैसे उसके प्रमुख निर्यात सेक्टर के लिए। उनका यह भी आरोप है कि समझौते में इमिग्रेशन और निवेश के मोर्चे पर जरूरत से ज्यादा रियायतें दी गई हैं। इसके बावजूद भारत के नजरिए से देखें तो यह समझौता संतुलित और दूरदर्शी दिखाई देता है, क्योंकि इसमें घरेलू हितों से कोई बड़ा समझौता नहीं किया गया है।

इस एफटीए का एक बड़ा और ऐतिहासिक पहलू शिक्षा और रोजगार से जुड़ा है। पहली बार किसी व्यापार समझौते में पढ़ाई के साथ काम करने, पोस्ट-स्टडी वर्क और प्रोफेशनल मोबिलिटी को कानूनी अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। न्यूज़ीलैंड में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को पढ़ाई के दौरान काम करने की गारंटी मिलेगी और डिग्री पूरी होने के बाद तीन से चार साल तक वहां काम करने का अवसर मिलेगा। इससे न केवल छात्रों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय अनुभव और कौशल भी मिलेगा, जो भारत लौटने पर देश के लिए फायदेमंद होगा।

इसके अलावा आईटी, इंजीनियरिंग, हेल्थकेयर, एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन और योग जैसे क्षेत्रों में हजारों भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए अस्थायी रोजगार के रास्ते खुलेंगे। फार्मा और मेडिकल डिवाइसेज सेक्टर में भारत के मानकों को मान्यता मिलने से निर्यात लागत घटेगी और भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। कृषि क्षेत्र में भी न्यूज़ीलैंड के साथ सहयोग से भारत में सेब, कीवी और शहद जैसी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण संदेश अमेरिका के लिए भी है। भारत यह दिखा रहा है कि वह अब केवल एक बाजार पर निर्भर नहीं रहेगा। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और न्यूज़ीलैंड जैसे देशों के साथ समझौते कर भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक व्यापार में उसकी स्थिति मजबूत हो रही है। इससे अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते में भी भारत की bargaining power बढ़ेगी।

आज न्यूज़ीलैंड में करीब तीन लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो वहां की तीसरी सबसे बड़ी आबादी हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश की संभावनाएं अभी पूरी तरह खुली नहीं हैं। ऐसे में यह एफटीए आने वाले 10-15 वर्षों में अरबों डॉलर के निवेश और व्यापार को नई गति दे सकता है। कुल मिलाकर, अमेरिका के दबाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत-न्यूज़ीलैंड एफटीए भारत की बदलती व्यापार नीति, आत्मनिर्भर सोच और वैश्विक मंच पर बढ़ते कद का स्पष्ट संकेत है।

अभियान

आचरण की शुद्धि से बदलता है भाग्य और शांत होते हैं ग्रह

मनुष्य प्रायः अपने जीवन की समस्याओं का कारण ग्रहों की स्थिति में खोजता है। कोई शनि को दोष देता है, कोई राहु-केतु को, तो कोई सूर्य या चंद्र की पीड़ा को अपने दुखों की जड़ मान लेता है। इसी कारण पूजा, पाठ, जप, यज्ञ, दान और रत्न धारण की ओर उसका ध्यान सबसे पहले जाता है। यह उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं और उनका अपना महत्व भी है, लेकिन जीवन के अनुभव यह भी बताते हैं कि केवल बाहरी उपायों से ग्रह स्थायी रूप से प्रसन्न नहीं होते। ग्रहों की वास्तविक शांति मनुष्य के आचरण, व्यवहार और सोच से जुड़ी हुई है। जैसे कर्म का सिद्धांत कहता है कि जैसा बोओगे, वैसा ही काटोगे, उसी प्रकार ग्रह भी मनुष्य के कर्म और आचरण के अनुसार ही फल देते हैं।

कर्म कभी नष्ट नहीं होता, उसका केवल रूप बदलता है। विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि पदार्थ का विनाश नहीं होता, केवल उसका रूपांतरण होता है। ठीक इसी तरह मनुष्य द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म, चाहे वह किसी के प्रति प्रेम का हो या घृणा का, सेवा का हो या अपमान का, एक ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। यही ऊर्जा समय आने पर सुख या दुख बनकर सामने आती है। ज्योतिष की भाषा में यही संचित कर्म ग्रहों के माध्यम से फलित होते हैं। इसलिए यदि हम अपने कर्म और आचरण को शुद्ध कर लें, तो ग्रहों की कठोरता अपने आप कम होने लगती है।

धर्मशास्त्रों में जीवन को संतुलित और सफल बनाने के जो सूत्र दिए गए हैं, वे केवल नैतिक उपदेश नहीं हैं, बल्कि गहरे ज्योतिषीय रहस्य भी अपने भीतर समेटे हुए हैं। 'मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, अतिथि देवो भव' जैसे वाक्य जीवन के व्यवहारिक नियम हैं। माता, पिता, गुरु और अतिथि के प्रति आदर का भाव रखने वाला व्यक्ति अनजाने में ही अपने जीवन के कई ग्रह दोषों को शांत कर लेता है। शास्त्र कहते हैं कि मात्र प्रणाम करने से, सदाचार के पालन से और वृद्धों की सेवा से आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है। यह वृद्धि केवल सामाजिक स्तर पर नहीं, बल्कि ग्रहों की अनुकूलता के रूप में भी दिखाई देती है।

ऋषि-महर्षियों ने यह स्पष्ट किया है कि नौ ग्रह केवल आकाश में घूमने वाले पिंड नहीं हैं। उनका प्रतिनिधित्व इस पूरे चराचर जगत में फैला हुआ है। पदार्थ, वनस्पति, पशु-पक्षी और मनुष्य के पारिवारिक व सामाजिक संबंधों में ग्रह अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी ग्रह का विशेष प्रभाव होता है, जो उसके स्वभाव, विचार, व्यवहार और जीवन की प्रमुख घटनाओं में झलकता है। सूर्य आत्मा और पिता का प्रतिनिधि है, चंद्र मन और माता का, मंगल पराक्रम और छोटे भाई-बहनों का, बुध बुद्धि और वाणी के साथ मामा व बंधुओं का, बृहस्पति ज्ञान और धर्म के साथ गुरुजन व वृद्धों का, शुक्र ऐश्वर्य और सुख के साथ जीवनसाथी का, शनि कर्म और दुख के साथ सेवक, श्रमिक और वंचित वर्ग का कारक माना गया है। राहु और केतु समाज के उन लोगों से जुड़े हैं, जो उपेक्षित, असहाय या मुख्य धारा से अलग होते हैं।

इस दृष्टि से देखा जाए तो ग्रहों को प्रसन्न करने का मार्ग अत्यंत सरल हो जाता है। यदि सूर्य निर्बल है और जीवन में आत्मविश्वास की कमी है, तो पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों के प्रति सम्मान और सेवा का भाव रखें। यदि चंद्र पीड़ित है और मन अशांत रहता है, तो माता और माता समान स्त्रियों की भावनाओं का आदर करें। मंगल के कष्ट में छोटे भाई-बहनों के साथ संबंध सुधारें और उनके प्रति सहयोगी बनें। बुध की पीड़ा में वाणी को मधुर रखें और संबंधियों से कटु व्यवहार न करें। बृहस्पति के अशुभ प्रभाव में गुरुजन और वृद्धों की सेवा करें तथा ज्ञान और धर्म के मार्ग पर चलें। शुक्र के कमजोर होने पर जीवनसाथी को कष्ट देना सीधे-सीधे ऐश्वर्य और सुख में कमी लाता है, इसलिए दांपत्य जीवन में प्रेम, सम्मान और संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। शनि के कष्ट में श्रमिकों, सेवकों और निर्धनों के प्रति करुणा और न्याय का भाव रखें। राहु के प्रभाव में अंगहीनों और उपेक्षित लोगों की सहायता करें और केतु के लिए दीन-हीन, रोगी और असहाय व्यक्तियों का सहारा बनें। अनुभव यह सिद्ध करता है कि यदि ग्रहों के प्रतिनिधि जीवों से हमारे संबंध बिगड़े हुए हों, तो पूजा-पाठ, जप-तप और दान भी अपेक्षित फल नहीं दे पाते। ग्रह केवल कर्मकांड से नहीं, बल्कि मनुष्य की चेतना और संवेदना से प्रसन्न होते हैं। जब आचरण शुद्ध होता है, विचार सकारात्मक होते हैं और व्यवहार करुणा से भरा होता है, तब ग्रहों की कठोरता स्वतः ही शांत होने लगती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ग्रहों की शांति का सबसे सशक्त और स्थायी उपाय मनुष्य का अपना आचरण है। जब जीवन प्रेम, सेवा, आदर और सदाचार की दिशा में बहने लगता है, तब भाग्य भी उसी दिशा में बदलने लगता है और ग्रह अनुकूल होकर जीवन में स्थिर सुख और शांति का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004 (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002 and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का पुलिस और प्रजा के बीच विश्वास का सेतु अधिक सुदृढ़ हो तथा प्रजा का पुलिस पर भरोसा ठोस बने; ऐसे वातावरण का निर्माण करने का प्रेरक आह्वान

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने गांधीनगर में दो दिवसीय राज्य स्तरीय क्राइम कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ कराया

▸▸ गुजरात पुलिस कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के अलावा क्राइम डिटेक्शन-प्रिवेंशन तथा कम्युनिटी आउटरीच सहित सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ कार्य कर रही है : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

▸▸ उप मुख्यमंत्री का जूनियर आईपीएस अधिकारियों से लेकर सीनियर आईपीएस अधिकारियों सहित सभी अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले नए विषयों और बेस्ट प्रैक्टिसेज को उदार मन से स्वीकार करने का अनुरोध

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारियों का आह्वान किया है कि वे पुलिस और प्रजा के बीच विश्वास का सेतु सुदृढ़ हो तथा प्रजा को पुलिस के साथ जुड़ने में कोई तकलीफ न रहे; ऐसे ठोस वातावरण का निर्माण करें।

उन्होंने कहा कि प्रजा के साथ सुदृढ़ संपर्क तथा प्रजा का पुलिस पर विश्वास ही क्राइम कंट्रोल के लिए हमारी आईबी है। उन्होंने इस संदर्भ में कहा कि गुजरात में जो शांति एवं सुरक्षा है, उसके परिणामस्वरूप हमने विकास के रोल मॉडल राज्य के रूप में गौरव प्राप्त किया है। इतना ही नहीं; ग्लोबल कंपनियाँ और उद्योग भी राज्य की इस शांति एवं सुरक्षा की स्थिति के कारण ही व्यापार-उद्योग के लिए गुजरात का चयन करती हैं।

उन्होंने इसका श्रेय राज्य पुलिस की सतर्कता, कर्तव्यनिष्ठा तथा कर्तव्यभावना को देते हुए पुलिस बल को अभिनंदन दिया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में गांधीनगर में राज्य स्तरीय क्राइम कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ कराया। इस दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस में राज्य पुलिस महानिदेशक सहित अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, रेंज पुलिस महानिरीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक भाग ले रहे हैं।

श्री पटेल ने इस कॉन्फ्रेंस को राज्य की जनता के भले तथा सुरक्षा के लिए नया विचार-चिंतन-मंथन प्रदान करने वाला

आयोजन बताया।

उन्होंने जोड़ा कि गुजरात पुलिस अपराध नियंत्रण एवं निवारण के लिए टेक्नोलॉजी के उपयोग से सज्ज है, परंतु अपराध करने वाले भी अब टेक्नोलॉजी का उपयोग करने लगे हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए पुलिस बेड़े में सतर्कता के साथ अधिक से अधिक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग आवश्यक हुआ है।

श्री भूपेंद्र पटेल ने इस बैठक में पुलिस बल में एआई का उपयोग, कोस्टल सिक्योरिटी, साइबर क्राइम रोकने के श्रेष्ठ कार्य करने को लेकर भी मार्गदर्शन दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस बल की जनोन्मुखी नीतियाँ और पुलिसिंग आदि व्यवस्थाएँ ठेठ ग्रामीण स्तर तक समान रूप से पहुँचें; यह भी वरिष्ठ अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने अपेक्षा व्यक्त की कि पुलिस ड्रग्स की लत के शिकार हुए युवाओं को सजा के बजाय प्रेम से समझाकर काउंसेलिंग से सही रास्ते पर लाने की दिशा में भी कार्यरत रहेगी और बैठक में इस संबंध में फलदायी चिंतन-मंथन होगा।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा कि गुजरात पुलिस कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के अलावा क्राइम डिटेक्शन-प्रिवेंशन तथा कम्युनिटी आउटरीच सहित सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ कार्य कर रही है। सामाजिक समस्याओं, असामाजिक तत्वों तथा साइबर अपराधियों के विरुद्ध गुजरात ने बाकायदा हल्लाबोल करके अद्भुत कार्य किया है। इसके लिए उन्होंने गुजरात पुलिस की समग्र टीम को अभिनंदन दिया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

▸▸ गुजरात देश के विकास का रोल मॉडल बना, जिसकी नींव शांति एवं सुरक्षा का वातावरण बनाए रखने वाले पुलिस बल की कर्तव्यनिष्ठा है

▸▸ एआई सहित अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से सज्ज तथा सतर्क पुलिस बल अपराधियों द्वारा टेक्नोलॉजी के उपयोग से होने वाले अपराधों पर नियंत्रण के लिए सक्षम है

श्री संघवी ने दो दिवसीय क्राइम कॉन्फ्रेंस के दौरान जूनियर आईपीएस अधिकारियों से लेकर सीनियर आईपीएस अधिकारियों सहित सभी अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले नए विषयों और बेस्ट प्रैक्टिसेज को उदार मन से स्वीकार करने का आह्वान करते हुए जोड़ा कि जब इस राष्ट्रीय स्तर की क्राइम कॉन्फ्रेंस के आयोजन का विचार किया गया, तब सभी शहर/जिले के डीसीपी/एसपी स्तरीय अधिकारियों का भी समावेश करने पर बल दिया गया, जिससे इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनके आइडिया साझा हों और उनके द्वारा किए जा रहे टेक्नोलॉजी के उपयोग तथा अलग-अलग क्षेत्रों में किए गए नए प्रयासों का आपसी आदान-प्रदान हो।

राज्य के मुख्य सचिव श्री एम. के. दास ने कहा कि राज्य में आयोजित होने वाली क्राइम कॉन्फ्रेंसेज का बहुत ही महत्व है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता तथा केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में आयोजित हुई डीजी-आईजी कॉन्फ्रेंस में हुई चर्चा के महत्वपूर्ण मुद्दों की जानकारी डाउन द लाइन फील्ड ऑफिसर तक पहुँचे; इसके लिए भी इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा होगी। इसके अलावा; बॉर्डर सिक्योरिटी, कोस्टल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम डिटेक्शन-प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन तथा ऑपरेशन सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

राज्य पुलिस महानिदेशक श्री विकास सहाय ने कहा कि क्लोज को-ऑर्डिनेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इस दो दिवसीय राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस में सभी शहर, रेंज के विभिन्न जिलों द्वारा बेस्ट प्रैक्टिसेज के संबंध में प्रेजेंटेशन के साथ आवश्यक चर्चा की जाएगी। इसके अलावा; साइबर क्राइम, नारकोटिक्स सहित वर्तमान चुनौतियों तथा उनके निवारण पर भी गहन चर्चा की जाएगी। गुजरात पुलिस की हर इकाई में श्रेष्ठ कार्य हो रहा है, जो प्रशंसनीय है। फिर भी हर व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश रहती है, जो तभी हो सकता है, जब आत्ममंथन तथा समीक्षा हो और इस समीक्षा तथा आत्ममनंथन के लिए क्राइम कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होती है।

इस अवसर पर सीआईडी क्राइम डीजीपी डॉ. के. एन. एल. राव, श्री जी. एस. मलिक, डॉ. नीरजा गोटरू सहित डीजीपी रैंक के अधिकारी, एडीजीपी, आईजीपी, डीआईजी तथा एसपी रैंक के आईपीएस अधिकारी उपस्थित रहे।

विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) : वीबी - जी राम जी (विकसित भारत – जी राम जी) अधिनियम, 2025 की प्रमुख विशेषताएँ

(जीएनएस)। **1.प्रस्तावना:** विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप समृद्ध एवं सुदृढ़ ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, विकास, अभिसरण और संतृप्ति को बढ़ाकर तथा इससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिनों की मजदूरी-रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान कर; एक ग्रामीण विकास रूपरेखा स्थापित करने के लिए अधिनियम।

2.विकसितभारतकेदृष्टिकोणके अनुरूपबढ़ीहुईआजीविकागारंटी: अकुशल शारीरिक श्रम करने इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिनों की मजदूरी-रोजगार की वैधानिक गारंटी प्राप्त होगी।

3.अधिनियमकेअंतर्गतशुरूकिएजानेवालेकार्य: इस विधान के अंतर्गत शुरू किए जाने वाले सभी कार्य एवं परियोजनाएँ विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक का अंग होंगी, जिनमें जल-संबंधी कार्यों के माध्यम से जल सुरक्षा, मूलभूत अवसंरचना, आजीविका-संबंधी अवसंरचना तथा प्रतिकूल मौसमीय घटनाओं के शमन हेतु कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

4.कार्यों की आयोजना: कार्यों की आयोजना विकसित ग्राम पंचायत आयोजना के माध्यम से की जाएगी, जिन्हें ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार किया जाएगा तथा इन्हें पीएम गति–शक्ति सहित राष्ट्रीय स्थानिक योजना प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जाएगा। पंचायतों की भौगोलिक स्थिति, नगरीकरण की दिशा में प्रगति आदि पर आधारित उनकी विविध विकासात्मक आवश्यकताओं को योजना निर्माण के दौरान ध्यान में रखा जाएगा।

5.कृषि के व्यस्ततम समय के दौरान पर्याप्त कृषि श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना: ग्रामीण कार्यबल के लिए बढ़ाई गई मजदूरी-रोजगार गारंटी को दृष्टिगत रखते हुए, विशेष रूप से बुवाई और कटाई के व्यस्ततम समय के दौरान, कृषि श्रम की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इस संदर्भ में, अधिनियम में राज्यों को एक वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर साठ दिन की अवधि अधिसूचित करने का प्रावधान होगा, जिसके अंतर्गत बुवाई एवं कटाई की व्यस्ततम समयावधि को सम्मिलित किया जा सकेगा तथा इस अवधि में इस अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित कार्य नहीं किए जाएंगे।

6.योजनाकास्वरूप: यह योजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में लागू की जाएगी। अधिनियम में विनिर्दिष्ट अनुसार, राज्य अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से छह माह के भीतर योजना को अधिसूचित करेंगे।

7.वित्तपोषणपद्धति: केन्द्र सरकार और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारों के बीच निधि-साझेदारी की पद्धति पूर्वोत्तर राज्यों तथा हिमालयी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रोंके लिए 90:10 तथा अन्य राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 60:40 होगी।

8.राज्यों को मानक आधारित आवंटन: केन्द्र सरकार, वस्तुनिष्ठ मानकों वाले एक संयुक्त सूचकांक के आधार पर प्रत्येक राज्य को मानक आधारित आवंटन करेगी और मानक आवंटन से अधिक व्यय की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होगी।

9.विशेषछूट: प्राकृतिक आपदाओं अथवा असाधारण परिस्थितियों के समय, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया जाए, विशेष छूट की अनुमति होगी, जिससे समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके एवं राहत हेतु प्रावधानों में अस्थायी संशोधन किया जा सके।

10.कार्यान्वयन संरचना: राष्ट्रीय स्तर की एक संचालन समिति योजना का समग्र पर्यवेक्षण करेगी तथा मानक आवंटनों के अनुमोदन एवं अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अन्य कार्यों के लिए उत्तरदायी होगी। राज्य संचालन समिति को राज्य में योजना के कार्यान्वयन का क्षेत्राधिकार होगा तथा यह राष्ट्रीय स्तर पर जारी निर्देशों के अनुरूप राज्य-विशिष्ट पर्यवेक्षण, निगरानी एवं नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

11.जिला कार्यक्रम समन्वयक: जिला कार्यक्रम समन्वयक,जिला स्तर पर योजना के अंतर्गत सभी कार्यकलापों के योजना-निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी एवं समन्वय के लिए प्राधिकृत अधिकारी होगा, जिसमें संबंधित सभी लाइन विभागों एवं प्राधिकरणों के साथ समन्वय शामिल होगा। ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी, योजना के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें यथा विहित रोजगार मांगों की पूर्ति एवं प्रबंधन, कार्यस्थलों का प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण तथा सहभागितापूर्ण योजना-निर्माण प्रक्रियाओं का सुगमीकरणसम्मिलित है। ग्राम पंचायत ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी करने, विकसित ग्राम पंचायत योजनाएँ तैयार करने तथा अधिनियम में विहित अन्य कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगी।

12.पंचायतीराज संस्थाओं (पीआरआई) की भूमिका: ग्राम पंचायत की प्राथमिक कार्यान्वयन भूमिका होगी तथा वह श्रमिकों का पंजीकरण करने, ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी करने तथा कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर कम से कम 50 प्रतिशत कार्यों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगी। ग्राम सभा नियमित सामाजिक अंकेक्षण भी करेगी। मध्यवर्ती पंचायतें,ब्लॉक-स्तरीय आयोजना, प्रस्तावों के समेकन एवं अभिसरण के सुगमीकरण पर ध्यान केंद्रित करेंगी। जिला पंचायतें, एक समर्पित संचालन समिति के माध्यम से, समग्र पर्यवेक्षण एवं निगरानी की जिम्मेदारी निभाएंगी तथा समेकित जिला योजनाएँ तैयार करने में जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) की सहायता करेंगी।

13. मजदूरी दर: अकुशल शारीरिक कार्यों हेतु मजदूरी दरें इस विधान के प्रयोजनार्थ केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएंगी। पृथक दरें अधिसूचित किए जाने तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) के अंतर्गत अधिसूचित मजदूरी दरें लागू मानी जाएंगी।

14. बेरोजगारी भत्ता: यदि किसी ग्रामीण परिवार को, मांग प्रस्तुत करने के पश्चात, निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य प्रदान नहीं किया जाता है, तो राज्य सरकार अनुसूची–II में विहित दरों एवं शर्तों के अनुसार बेरोजगारी भत्ता का भुगतान करने के लिए बाध्य होगी।

15. पारदर्शिता एवं जवाबदेही: पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण, स्थानिक प्रौद्योगिकी आधारित (स्पैटियल टेक्नालॉजी) आयोजना, मोबाइल एवं डैशबोर्ड आधारित निगरानी तथा साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण प्रणालियों के माध्यम से प्रावधान किए जाएंगे। सामाजिक अंकेक्षण तंत्र को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा।

8,800 से अधिक जहाज़ रीसाइक्लिंग और 32% वैश्विक योगदान के साथ अलंग बना शिप रीसाइक्लिंग का "ग्रीन मॉडल"

▸▸ 2025-26 की शुरुआत से ही जहाज़ों के आगमन में दिखी तेजी, 13% की वृद्धि दर्ज

▸▸ अगले 10 वर्षों में 15,000 जहाज़ों का रीसाइक्लिंग करने का महत्वाकांक्षी विज़न

▸▸ GMB के 1224 करोड़ के मास्टर प्लान से अलंग की शिप रीसाइक्लिंग क्षमता होगी दोगुनी

▸▸ आगामी VGRC में कच्छ और सौराष्ट्र के मंच से अलंग की 40 वर्षों की उपलब्धियों का होगा वैश्विक प्रदर्शन

(जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तैयार है। कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए आयोजित वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (VGRC) का दूसरा संस्करण जनवरी 2026 में राजकोट में होने जा रहा है जहाँ राज्य अपनी बढ़ती समुद्री ताकत को वैश्विक मंच पर अधिक मजबूती से पेश करेगा। इस आयोजन के केंद्र में है अलंग-सोसिया शिप रीसाइक्लिंग यार्ड, जिसे गुजरात मेरीटाइम बोर्ड के नेतृत्व में विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व में, गुजरात सरकार ने पारदर्शी शासन, ठोस नीतियाँ, कड़े सुरक्षा मानक और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को अपनाया है। इन सब प्रयासों के चलते अलंग आज केवल गुजरात ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की समुद्री विकास यात्रा का एक सशक्त और प्रेरक उदाहरण बनकर उभरा है।

अब तक 8,800 से अधिक जहाज़ों की हुई रीसाइक्लिंग, प्राप्त सामग्री का 99.95 प्रतिशत का हो रहा पुनः उपयोग

अलंग विश्व के सबसे बड़े शिप रीसाइक्लिंग बाजारों में से एक है और वैश्विक शिप रीसाइक्लिंग क्षेत्र में 32% का योगदान देता है। अब तक यहाँ 8,800 से अधिक जहाज़ों का सुरक्षित और नियमित रीसाइक्लिंग किया जा चुका है। इन जहाज़ों से प्राप्त सामग्री का लगभग 99.95% पुनः उपयोग में लाया जाता है जिससे अलंग शिप रीसाइक्लिंग में उभरता हुआ "ग्रीन मॉडल" बन गया है।

रीसाइक्लिंग सामग्री का अधिकतम पुनःउपयोग होने के कारण अलंग में कई डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए स्थिर व्यवसाय के अवसर मौजूद हैं। स्क्रैप प्रोसेसिंग, स्टील रोलिंग, मशीनरी रिफर्बिशमेंट, ट्रेडिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में लगातार आर्थिक गतिविधि और रोजगार के अवसर विकसित होते हैं।

इतना ही नहीं, अलंग में वर्तमान में 128 में से 115 प्लॉट पूरी तरह "हांगकांग कन्वेंशन (HKC) कम्प्लायंट" हैं, और जून 2025 से HKC के वैश्विक स्तर पर लागू होने के साथ ही अलंग को विश्व के सबसे विश्वसनीय ग्रीन रीसाइक्लिंग सेंटर के रूप में मान्यता मिली है।

2025-26 की शुरुआत से ही जहाज़ों के आगमन में दिखी तेजी, 13% की वृद्धि दर्ज

वर्ष 2024-25 के दौरान वैश्विक चुनौतियों के बीच भी अलंग ने अच्छा प्रदर्शन दर्ज किया और 113 जहाज़ों का रीसाइक्लिंग किया। वर्ष 2025-26 की शुरुआत में जहाज़ों के आगमन में 13 प्रतिशत वृद्धि दर्ज होने से क्षेत्र में सकारात्मक गति देखने को मिल रही है।

इसी दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने 2025 में अलंग के लिए एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है जिसके तहत आने वाले 10 वर्षों में 15,000 जहाज़ों का रीसाइक्लिंग करने का मिशन भी रखा गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा हेल्थकेयर, श्रमिक सुविधाएँ, समुद्री कौशल प्रशिक्षण और पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों को और मजबूत करने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है।

GMB के 1224 करोड़ के मास्टर प्लान से अलंग की शिप रीसाइक्लिंग क्षमता होगी दोगुनी

भविष्य में बढ़ते शिप रीसाइक्लिंग वॉल्यूम को ध्यान में रखते हुए, गुजरात मेरीटाइम बोर्ड (GMB) ने लगभग 1224 करोड़ की लागत से अलंग का मास्टर प्लान पूरा कर लिया है।

इस योजना के लागू होने के बाद वर्तमान 4.5 मिलियन LDT की रीसाइक्लिंग क्षमता दोगुनी होकर 9 मिलियन LDT तक पहुँच जाएगी, जिससे अलंग वैश्विक स्तर पर सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को और बढ़ा सकेगा। अलंग की इन उपलब्धियों के बीच गुजरात सरकार राजकोट में 10 से 12 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में अलंग को सिर्फ एक रीसाइक्लिंग यार्ड के रूप में नहीं बल्कि गुजरात की समुद्री शक्ति, ग्रीन टेक्नोलॉजी और निवेश के अनुकूल बिज़नेस सेंटर के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करेगी। राज्य सरकार को भरोसा है कि यह सम्मेलन राज्य की समुद्री क्षमताओं और भविष्य के अवसरों को वैश्विक स्तर पर उजागर करने का बेहतरीन मंच साबित होगा।

तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में संशोधन

(जीएनएस)। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, पश्चिम रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू करने जा रही है। अब तत्काल टिकट केवल सिस्टम द्वारा जनरेट किए गए वन टाइम पासवर्ड (OTP) के प्रमाणीकरण के बाद ही जारी किए जाएंगे। यह ओटीपी टिकट बुकिंग के समय यात्री द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा तथा ओटीपी के सफल सत्यापन के पश्चात ही टिकट जारी किया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ओटीपी आधारित तत्काल प्रमाणीकरण प्रणाली पहले ही पश्चिम रेलवे से प्रारंभ होने वाली 21 ट्रेनों में लागू की जा चुकी है। अब यह ओटीपी आधारित तत्काल प्रमाणीकरण प्रणाली 24 दिसम्बर, 2025 से निम्नलिखित चार और ट्रेनों में भी लागू की जा रही है:-

1. ट्रेन संख्या 14702 बांद्रा टर्मिनस – श्री गंगानगर एक्सप्रेस
2. ट्रेन संख्या 19037 बांद्रा टर्मिनस – बरौनी एक्सप्रेस
3. ट्रेन संख्या 19483 अहमदाबाद – सहरसा एक्सप्रेस
4. ट्रेन संख्या 22956 भुज – बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस

यह नई प्रणाली कम्प्यूटरीकृत पीआरएस काउंटरों, अधिकृत एजेंटों, आईआरसीटीसी वेबसाइट तथा आईआरसीटीसी मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाने वाली तत्काल बुकिंग पर लागू होगी। इस बदलाव का उद्देश्य तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा वास्तविक यात्रियों को तत्काल टिकट प्राप्त करने में बेहतर सुविधा प्रदान करना है।

यात्रियों को सलाह दी जाती है कि बुकिंग के समय एक वैध एवं सुगम मोबाइल नंबर अवश्य प्रदान करें, ताकि ओटीपी सत्यापन प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके। पश्चिम रेलवे सभी यात्रियों से इस महत्वपूर्ण बदलाव पर ध्यान देने का आग्रह करती है।

कांदिवली–बोरीवली सेक्शन पर छठी लाइन के कार्य के संबंध में पश्चिम रेलवे का मेजर ब्लॉक

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा कांदिवली–बोरीवली सेक्शन पर छठी लाइन के कार्य को पूरा करने के लिए 30 दिनों का ब्लॉक लिया जाएगा। यह ब्लॉक 20/21 दिसम्बर, 2025 की रात्रि से प्रारंभ होकर 18 जनवरी, 2026 तक जारी रहेगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बोरीवली में अप एवं डाउन स्लो लाइनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (EI) पैनल के कमीशनिंग कार्य हेतु 26 एवं 27 दिसम्बर, 2025 को 23:00 बजे से 07:00 बजे तक एक मेजर नॉन-इंटरलॉकिंग ब्लॉक लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 26 दिसम्बर, 2025 को 23:00 बजे से 27 एवं 28 दिसम्बर, 2025 की मध्यरात्रि तक कांदिवली और दहीसर के बीच डाउन फास्ट लाइन पर गति प्रतिबंध भी लागू रहेगा।

इस ब्लॉक के कारण कुछ उपनगरीय सेवाएं निरस्त रहेंगी तथा कुछ बोरीवली/अंधेरी लोकल ट्रेनें गोरेगांव तक ही चलाई जाएंगी।

ब्लॉक के कारण प्रभावित होने वाली ट्रेनों का विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है।

परिशिष्ट–I: 26/27 दिसम्बर, 2025 को ब्लॉक के दौरान गोरेगांव तक चलाकर वहीं से रिटर्न की जाने वाली ट्रेनें।

परिशिष्ट–II: 26/27 दिसम्बर, 2025 को निरस्त की जाने वाली ट्रेनें।

परिशिष्ट–III: 27 दिसम्बर, 2025 को निरस्त की जाने वाली ट्रेनें।

नोट: उपनगरीय लोकल ट्रेनों पर पड़ने वाले प्रभाव की सूचना यथासमय दी जाएगी। 31 दिसम्बर, 2025 के लिए नववर्ष समारोह को ध्यान में रखते हुए असामान्य निरस्तीकरण न हों, इसके लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक ने भावनगर मंडल के कर्मचारी को संरक्षा पुरस्कार से किया सम्मानित

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने सुरक्षित रेल परिचालन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 11 कर्मचारियों को दिनांक 22.12.2025 को पश्चिम रेलवे मुख्यालय, मुंबई में आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया। यह सम्मान नवंबर 2025 के दौरान ड्यूटी के समय उनकी असाधारण सतर्कता, सजगता एवं समर्पण के कारण संभावित अप्रिय घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रदान किया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने सभी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सजगता एवं कर्तव्यनिष्ठा रेलवे सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है और वे अन्य कर्मचारियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि भावनगर मंडल के लाठीदड रेलवे स्टेशन पर कार्यरत श्री घनश्याम सी. (कांटेवाला) को रेल परिचालन की संरक्षा से संबंधित उच्च स्तर की प्रतिबद्धता एवं सतर्कता के लिए महाप्रबंधक संरक्षा पुरस्कार (GM Safety Award) से सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि दिनांक 20.11.2025 को लाठीदड स्टेशन से एक मालगाड़ी पास थ्रू हो रही थी। उसी दौरान समपार फाटक पर तैनात श्री घनश्याम सी. (कांटेवाला) ने मालगाड़ी के सातवें एवं आठवें वैगन में हॉट एक्सल के कारण पहियों के अत्यधिक गर्म (रेड हॉट) होने की स्थिति को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने बिना विलंब किए गेट फोन के माध्यम से स्टेशन मास्टर को सूचित किया। स्टेशन मास्टर ने तत्परता से वॉकी-टॉकी के माध्यम से लोको पायलट को जानकारी दी, जिसके फलस्वरूप गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में रोक दिया गया। इसके बाद सहायक लोको पायलट द्वारा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की गई और स्थिति सामान्य होने पर मालगाड़ी को गंतव्य के लिए सुरक्षित रूप से रवाना किया गया। भावनगर मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने श्री घनश्याम सी. (कांटेवाला) को महाप्रबंधक संरक्षा पुरस्कार प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई दी तथा कहा कि कर्मचारी की त्वरित सोच, सतर्कता एवं जिम्मेदाराना कार्यशैली के कारण एक संभावित गंभीर दुर्घटना को समय रहते टालना संभव हो सका। उन्होंने इसे रेल संरक्षा के प्रति भावनगर मंडल की प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण बताया।

गुजरात पुलिस में नवनियुक्त 11,607 उम्मीदवारों को चयन पत्र प्रदान किए गए

चयन पत्र केवल सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी, अनुशासन के पालन और राष्ट्र सेवा का संकल्प लेने का अवसर है – मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को राज्य पुलिस बल में नए चयनित युवा पुलिस कर्मियों को प्रेरित करते हुए कहा कि चयन पत्र केवल सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी, अनुशासन के पालन और राष्ट्र सेवा का संकल्प लेने का अवसर है।

पुलिस बल की भर्तियों में उत्तीर्ण होकर लगभग 3,100 युवतियों सहित 11 हजार से अधिक युवा 'टीम गुजरात' शामिल हुए हैं।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, राज्य मंत्री श्री कमलेशभाई पटेल, गांधीनगर की महापौर श्रीमती मीराबेन पटेल, विधायक श्रीमती रीटाबेन पटेल सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में गांधीनगर में चयन पत्र प्रदान किए।

मुख्यमंत्री ने इन युवा एवं उत्साहवर्धक नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को मानव सेवा के धर्म और राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए सदैव कर्तव्यरत रहने की सीख दी।

इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि कानून लागू कराने वाले पुलिसकर्मी को कर्तव्य पालन में मानवाधिकारों का सम्मान, संवैधानिक मूल्यों का पालन और निष्पक्षता बनाए रखना आवश्यक है।

जब कोई व्यक्ति संकट में होता है, तब सहायता के लिए सबसे पहले पुलिस को याद करता है, यह कहते हुए मुख्यमंत्री ने आचरण में विनम्रता, वाणी में मधुरता और कार्य में निष्ठा को पुलिस सेवा की प्राथमिकता बनाने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए POLICE शब्द के विशेष अर्थ की विस्तृत व्याख्या की। उन्होंने कहा कि P यानी पोलाइट – जनता के प्रति हमेशा विनम्र और सहृदयभाव के साथ काम करता हो,

O यानी ऑबिडिएंट जो हमेशा – अधिकारियों की आज्ञा में रहकर ड्यूटी निभाता हो, L यानी लोयल, भारत के संविधान, नियम-कानून के प्रति वफादार रहकर, उसका पालन करते हुए कार्य करता हो,

I यानी इंटेलिजेंट – सदैव सतर्क और बुद्धिचातुर्य से कार्य करता हो,

C यानी करेजियस, किसी भी परिस्थिति में साहस न हारने वाला, हरेक फ्रंट पर वो लड़ने के लिए सज्ज हो, E यानी एन्थुजियास्टिक, उत्साही हो, जनता की सेवा एवं सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर हो, राष्ट्रहित सर्वोपरि का भाव हृदय में रखता हो।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दिए पुलिस के इस मर्म को पुलिस बल में नए मिल होने वाले कर्मी भी 'नागरिक देवो भवः' के ध्येय के साथ चरितार्थ करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री ने स्मार्ट पुलिसिंग की प्रधानमंत्री की सोच को साकार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा पुलिसमॉडर्नाइजेशन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।

उन्होंने जोड़ा कि राज्यव्यापी सीसीटीवी नेटवर्क, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, बॉडी वॉर्न कैमरा, साइबर आश्वस्त – इबर सेफ प्रोजेक्ट जैसे उपायों से राज्य का पुलिस बल टेक्नॉलोजी से सशक्त हुआ है।

उन्होंने नवनियुक्त कर्मियों से कहा कि नए शामिल हो रहे युवा टेक्नोसेवी हैं, जिससे अधिक क्षमता निर्माण होगा र विकसित भारत 2047 में विकसित-सुरक्षित-समृद्ध गुजरात लीड लेगा।

राज्य मंत्री श्री कमलेश पटेल की विशेष उपस्थिति

-:मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल-:

- पुलिस बल में नए शामिल होने वाले कर्मी भी 'नागरिक देवो भवः' के ध्येय को साकार करेंगे
- जब कोई व्यक्ति संकट में होता है, तब सहायता के लिए सबसे पहले पुलिस को याद करता है
- राज्य सरकार पुलिस मॉडर्नाइजेशन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है
- राज्यव्यापी सीसीटीवी नेटवर्क, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, बॉडी वॉर्न कैमरा, साइबर आश्वस्त – साइबर सेफ प्रोजेक्ट जैसे आयामों से पुलिस बल टेक्नॉलोजी संपन्न बना है
- जब कोई नागरिक अपनी समस्या लेकर आए, तो उसके दुःख में सहभागी बनकर पूरे दिल से सहायक होना– उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

नवनियुक्त 11,607 उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा कि गुजरात पुलिस का अभिन्न अंग बनने के साथ वर्दी के रूप में आप सभी को समाज की बुराइयों को मिटाने की शक्ति मिली है। यह वर्दी हमें दिन-रात, सर्दी-गर्मी, त्यौहार या प्राकृतिक आपदा जैसी किसी भी कठिन परिस्थिति में जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर रहने की शक्ति देती है।

उन्होंने कहा कि आप सभी नवनियुक्त उम्मीदवार नई ऊर्जा और नए जोश के साथ ऐसा कार्य करें, जिससे वर्दी की गरिमा और सम्मान निरंतर बढ़े।

जब भी कोई नागरिक अपनी समस्या लेकर आपके पास आए, तो उसके दुःख में सहभागी बनकर पूरे दिल से उसकी सहायता करने का प्रयास करें।

उप मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में पहली बार उम्मीदवारों से नियुक्ति के लिए जिले का चयन लिया जाएगा, ताकि उन्हें अपने मूल या निकटवर्ती जिले में नियुक्ति मिल सके। इसके अतिरिक्त; उन्होंने जोड़ा कि जनवरी महीने के अंत तक नई भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षा आयोजित करने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

गुजरात पुलिस परिवार का हिस्सा बने जवानों को प्रेरणा देते हुए राज्य मंत्री श्री कमलेश पटेल ने कहा कि वर्दी धारण करने के बाद भी एक सामान्य नागरिक की तरह हमेशा अपने गांव, शहर और मित्रों से जुड़े रहना। पद से जुड़े संबंध केवल पद रहने तक ही सीमित होते हैं, लेकिन स्नेह और भावनाओं के संबंध सेवानिवृत्ति के बाद भी अटूट बने रहते हैं। आपके माता-पिता ने दिन-रात परिश्रम करके आपको इस मुकाम तक पहुँचाने का जो सपना देखा था, वह आज साकार हुआ है। उनके चरण स्पर्श कर अवश्य आशीर्वाद लेना।

-:उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी-:

- नवनियुक्तों को गुजरात पुलिस का अभिन्न अंग बनने के साथ वर्दी के स्वरूप में समाज की बुराइयों को समाप्त करने की शक्ति प्राप्त हुई है
- राज्य में पहली बार उम्मीदवारों से नियुक्ति के लिए जिले का चयन मांगा जाएगा, निकट से निकट पोस्टिंग मिल सके ऐसे प्रयास
- जनवरी महीने के अंत तक नई भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षा आयोजित करने की तैयारियां

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री एम. के. दास ने कहा कि भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष डॉ. नीरजा गोटरू और उनकी टीम ने बिना किसी शिकायत के समग्र भर्ती प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण की है।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में पिछले एक महीने में विभिन्न विभागों में लगभग 40 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्तियां दी गई हैं।

मुख्य सचिव श्री दास ने कहा कि जब नागरिक आपके पास आते हैं, तब आपकी जिम्मेदारी केवल कानून का पालन करवाने की ही नहीं, बल्कि न्याय और मानवता की रक्षा करने की भी होती है। पुलिस की वर्दी केवल सत्ता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह जन विश्वास, ईमानदारी और अनुशासन का प्रतीक है तथा नागरिकों के मन में सुरक्षा का छाप स्थापित करता है। उन्होंने जोड़ा कि कानून की रक्षा के लिए कठोर होना आवश्यक है, लेकिन उसके साथ-साथ मानवता और संवेदनशीलता भी उतनी ही आवश्यक है। इस प्रकार समाज की शांति और सुरक्षा के लिए आपका योगदान अमूल्य है।

गुजरात पुलिस के महानिदेशक श्री विकास सहाय ने पुलिस बल की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से पूर्ण करने के लिए गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष को बधाई देते हुए कहा कि जब हम 'विकसित भारत - विकसित गुजरात' के संकल्प की परिकल्पना करते हैं, तो वह तभी संभव हो सकती है जब नागरिकों को सुरक्षा और संरक्षा की अनुभूति हो। नागरिकों में सुरक्षा और संरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने के लिए गुजरात पुलिस वर्षों से प्रशंसनीय कार्य कर रही है। इसी कार्य के परिणामस्वरूप गुजरात मॉडल की चर्चा न केवल देश में, बल्कि विदेशों में भी हो रही है।

गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष डॉ नीरजा गोटरू ने गुजरात पुलिस में चयनित नए उम्मीदवारों को बधाई देते हुए कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया में राज्यभर से 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने शारीरिक परीक्षा में भाग लिया था। शारीरिक परीक्षा पूर्ण होने के बाद 2.45 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा दी, जिनमें से 32 हजार से अधिक उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया। इसके बाद प्रोविजनल सूची तैयार कर लोक रक्षक कैडर में कुल 11,899 उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया की गई, जिनमें से 8,782 पुरुष और 3,117 महिला उम्मीदवारों का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि यह पूरी प्रक्रिया बायोमेट्रिक सहित विभिन्न टेक्नॉलोजी के उपयोग से पारदर्शी रूप से आयोजित की गई।

इस चयन पत्र वितरण समारोह में गांधीनगर की महापौर श्रीमती मीराबेन पटेल, विधायक श्रीमती रीटाबेन पटेल, पुलिस महानिदेशक (सीआईडी क्राइम एंड रेलवे) डॉ. के.एल.एन. राव, अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर श्री ज्ञानेंद्र सिंह मलिक, श्री राजू भार्गव, गृह सचिव सुश्री निपुणा तोरवणे, पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस विभाग में भर्ती हुए उम्मीदवार उपस्थित रहे।

विकसित बिहार के संकल्प को घर-घर तक पहुंचाने की तैयारी, सात निश्चय-3 के प्रचार को मिली नई रफ्तार

(जीएनएस)। पटना। बिहार को विकसित राज्य बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सात निश्चय-3 की जानकारी अब हर घर तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सात निश्चय-3 से जुड़ी सभी योजनाओं, उद्देश्यों और उपलब्धियों का प्रभावी, तथ्यात्मक और व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता तक सरकार की मंशा और कार्य स्पष्ट रूप से पहुंच सके। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार की योजनाओं को लेकर किसी भी प्रकार की गलत सूचना या अफवाह को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जैसे ही किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी सामने आए, उसका तुरंत खंडन किया जाए और सही तथ्यों को जनता के सामने रखा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जनसंपर्क विभाग की भूमिका केवल सूचना देने तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार और जनता के बीच सेतु बनकर भरोसे और पारदर्शिता को मजबूत करना भी उसकी जिम्मेदारी है।

बैठक में बताया गया कि सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और विकास कार्यों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए मल्टी-प्लेटफॉर्म रणनीति पर काम किया जा रहा है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो और डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ-साथ सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों जैसे फेसबुक, यूट्यूब, एक्स और इंस्टाग्राम का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा आउटडोर होर्डिंग्स, फ्लेक्स, चैटबॉट और डिजिटल इन्फ्लूएंसर्स के जरिए भी सात निश्चय-3 की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने की योजना है, ताकि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अधिकतम लोगों तक सरकार की बात पहुंचे।

सात निश्चय-3 के प्रचार-प्रसार के लिए सरकार ने 15 प्रमुख विषयों को केंद्र में रखा है। इनमें रोजगार सृजन, विधि-व्यवस्था, पर्यटन विकास, महिला सशक्तिकरण, पुलिस आधुनिकीकरण, नगर विकास, औद्योगिक विकास, जलवायु परिवर्तन से निपटने की रणनीति, आधारभूत संरचना का विस्तार, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और खेल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। इन सभी विषयों के जरिए सरकार यह संदेश देना चाहती है कि विकास केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग और हर जरूरत को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जा रही हैं।

समीक्षा बैठक में यह भी बताया गया कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग प्राकृतिक आपदा, शांति व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आपात स्थितियों में सही और प्रमाणिक सूचना का त्वरित प्रसार कर अफवाहों पर लगाम लगाने का काम किया जाता है। साथ ही जनता से मिलने वाले फीडबैक को विभिन्न माध्यमों से एकत्र कर संबंधित विभागों और सरकार तक पहुंचाया जाता है, ताकि नीतियों और योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। बैठक के दौरान विभाग की प्रमुख योजनाओं की भी जानकारी दी गई। इनमें क्षेत्रीय प्रचार योजना, विशेष अंगीभूत योजना, जनजातीय क्षेत्र उप-योजना, बिहार राज्य पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना, बिहार डायरी एवं कैलेंडर का प्रकाशन, राज्य सूचना केंद्र का संचालन, आउटडोर पब्लिसिटी, पत्रकारों का प्रमाणीकरण और उनके कल्याण से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं के जरिए न केवल सरकारी सूचनाओं का प्रसार किया जा रहा है, बल्कि पत्रकारों के हितों का भी ध्यान रखा जा रहा है।

कफ सिरप तस्करी गिरोह पर पुलिस का शिकंजा, 50 हजार के इनामी सरगना समेत चार फरार

(जीएनएस)। वाराणसी। कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी से जुड़े एक बड़े नेटवर्क के खिलाफ वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में 50 हजार रुपये के इनामी सरगना शुभम जायसवाल सहित चार फरार आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। यह कदम आरोपियों के देश से बाहर भागने या छिपकर तस्करी के नेटवर्क को संचालित करने की आशंका को देखते हुए उठाया गया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि किसी भी हाल में आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि जिन चार आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, उनमें शुभम जायसवाल के अलावा आकाश पाठक, दिवेश जायसवाल और अमित जायसवाल शामिल हैं। ये सभी लंबे समय से फरार चल रहे हैं और इनके खिलाफ लगातार दबिश दी जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष जांच टीम यानी एसआईटी का गठन किया गया है, जो विभिन्न संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस कमिश्नर ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि किसी को इन आरोपियों के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि तस्करी के इस नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। पुलिस जांच में सामने आया है कि ये सभी आरोपी कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध खरीद-बिक्री में सीधे तौर पर शामिल थे और फर्जी कंपनियों के सहारे करोड़ों रुपये का कारोबार कर रहे थे। जांच के अनुसार, रांची की शैली ट्रेडर्स नामक फर्म का संचालन मुख्य सरगना शुभम जायसवाल करता था, जबकि डीएसए फार्मा नाम की फर्म दिवेश जायसवाल के नाम पर पंजीकृत थी। इसके अलावा काजीपुरा खुर्द निवासी अमित जायसवाल और गोलघर क्षेत्र के सिद्ध माता लेन निवासी आकाश पाठक भी इस नेटवर्क में अहम भूमिका निभा रहे थे। पुलिस का कहना है कि यह पूरा गिरोह योजनाबद्ध तरीके से नशीले कफ सिरप की सप्लाई कर रहा था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, शुभम जायसवाल वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र के प्रहलाद घाट कायस्थ टोला का निवासी है और उस पर पहले ही 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया जा चुका है।

फियो ने 9वें और 10वें उत्तरी क्षेत्र निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कारों में उत्तरी भारत के उत्कृष्ट निर्यातकों को सम्मानित किया

(जीएनएस)। नई दिल्ली, 23 दिसंबर, 2025: फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन्स (फियो) ने 23 दिसंबर, 2025 को नई दिल्ली में 9वें और 10वें उत्तरी क्षेत्र निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कारों का आयोजन किया, ताकि भारत के निर्यात विकास में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए उत्कृष्ट निर्यातकों को सम्मानित किया जा सके। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने प्रदान किए।

राज्य स्तर पर उत्कृष्टता को पहचानने और उच्च प्रदर्शन करने वाले निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित, फियो के क्षेत्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार उन उद्यमों का सम्मान करते हैं जिन्होंने उल्लेखनीय विकास, नवाचार, गुणवत्ता के प्रति जागरूकता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा दिखाई है। उत्तरी क्षेत्र, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर और चंडीगढ़ शामिल हैं, भारत के निर्यात प्रदर्शन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने सभा को संबोधित करते हुए पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उनके लचीलेपन और योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि लगातार वैश्विक अनिश्चितताओं, आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटों और भू-राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद, भारत ने एक मजबूत और लचीला निर्यात प्रदर्शन बनाए रखा है।

उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में कुल निर्यात में 5.43 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस अवधि के दौरान मर्चेंडाइज निर्यात बढ़कर 292 बिलियन डॉलर हो गया। निर्यात सेक्टर की मज़बूती 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य हासिल करने में और मदद करेगी। यह प्रदर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सेवाओं, पेट्रोलियम उत्पादों, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों जैसे क्षेत्रों में मजबूत विकास से प्रेरित है, जो भारत की निर्यात टोकरी के विविधीकरण और तकनीकी गहराई को उजागर करता है।

श्री अग्रवाल ने विदेश व्यापार नीति के माध्यम से एक स्थिर और सुविधाजनक नीतिगत माहौल बनाने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिसमें व्यापार सुविधा, डिजिटलीकरण, अनुपालन बोझ में कमी और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में निर्बाध एकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने व्यापार करने में आसानी और लेनदेन लागत को कम करने में पेपरलेस प्रणालियों के सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला।वाणिज्य सचिव ने आगे कहा कि ट्रेड कनेक्ट पोर्टल को जारी रखते हुए, सरकार अनुपालन का बोझ और कम करने के लिए भारत ट्रेड नेट लाने की योजना बना रही है।

उन्होंने यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ओमान और न्यूज़ीलैंड के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के ज़रिए भारत की बढ़ती ग्लोबल ट्रेड भागीदारी के बारे में भी बताया, साथ ही यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, इज़राइल, चिली, पेरू और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ बातचीत में हुई महत्वपूर्ण प्रगति का भी ज़िक्र किया।

फियो अध्यक्ष श्री एस. सी. रल्हन ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और उनकी उद्यमी भावना और ग्लोबल प्रतिस्पर्धा की सराहना की। उन्होंने कहा कि भू-राजनीतिक तनाव, सप्लाई चेन में रुकावटें, कमोडिटी की कीमतों में उतार-चढ़ाव, और प्रमुख बाज़ारों में आर्थिक मंदी जैसी चुनौतियों के बावजूद, भारतीय निर्यातकों ने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में उभरते अवसरों का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है।

उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, कपड़ा, प्रोसेस्ड फूड, कृषि और ग्रीन टेक्नोलॉजी सहित क्षेत्रों में मज़बूत विकास की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। रीजनल चेयरमैन (उत्तरी क्षेत्र), फियो श्री अरविंद गोयनका ने अपने स्वागत भाषण में, माननीय वाणिज्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारियों, गणमान्य व्यक्तियों और पुरस्कार विजेताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कपड़ा, हथकरघा, कालीन, खेल के सामान, इंजीनियरिंग सामान, हस्तशिल्प, ऑटोमोबाइल, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सेवाओं और ई-कॉमर्स क्षेत्रों में उत्तरी क्षेत्र के मज़बूत निर्यात आधार पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उत्तरी राज्यों ने "ज़िलों को निर्यात हब" पहल के तहत राज्य निर्यात संवर्धन नीतियों और ज़िला निर्यात कार्य योजनाओं के साथ सक्रिय निर्यात-आधारित विकास पहलों को अपनाया है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड सहित प्रमुख राज्य सामूहिक रूप से सालाना 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निर्यात करते हैं।

उन्होंने बताया कि क्लस्टर विकास, ओपीओडी -लिंक्ड निर्यात, लॉजिस्टिक्स पार्क, और निर्यातक सुविधा सेल जैसी केंद्रित पहलें एमएसएमई, कारीगरों और पहली बार निर्यात करने वालों को वैश्विक बाज़ारों तक पहुँचने और बड़े पैमाने पर रोज़गार पैदा करने के लिए सशक्त बना रही हैं। फियो के डीजी और सीईओ डॉ. अजय सहाय ने अपने समापन भाषण में, निर्यातकों के लिए प्रक्रियाओं को मज़बूत करने, उन्नत टेक्नोलॉजी अपनाने, विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक्स बनाने और बाज़ारों और उत्पादों में विविधता लाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, 5G विस्तार, डिजिटल पेमेंट, स्थायी विनिर्माण और कुशल मैनपावर में भारत की ताकतें निर्यात वृद्धि के अगले चरण को आगे बढ़ाएंगी और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के विज़न में योगदान देंगी।

9वें और 10वें उत्तरी क्षेत्र निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 ने उन निर्यातकों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित किया जिन्होंने भारत के व्यापार विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फियो ने निर्यातकों को सपोर्ट करने, नए अवसरों को बढ़ावा देने और भारत को एक प्रमुख ग्लोबल ट्रेडिंग देश के रूप में उभरने में मदद करने के लिए सरकार के साथ साझीदारी करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

सोना वायदा 1.38 लाख रुपये और चांदी वायदा 2.16 लाख रुपये के स्तर के पार पहुँचा: क्रूड ऑयल में 17 रुपये का सुधार

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 251048.82 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 36079.35 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 214960.4 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का दिसंबर वायदा 34290 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2469.44 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 28410.90 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 138297 रुपये के भाव पर खूलकर, 138444 रुपये के ऑल टाइम हाई और 137826 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 136744 रुपये के पिछले बंद के सामने 1448 रुपये या 1.06 फीसदी की तेजी के संग 138192 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-गिनी दिसंबर वायदा 1052 रुपये या 0.97 फीसदी की बढ़त के साथ 110045 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-पेटल दिसंबर वायदा 153 रुपये या 1.12 फीसदी की बढ़त के साथ 13785 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। सोना-मिनी जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 134900 रुपये के भाव पर खूलकर, 136888 रुपये के दिन के उच्च और 134900 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 1452 रुपये या 1.08 फीसदी की बढ़त के साथ 136090 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-टेन दिसंबर वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 136136 रुपये के भाव पर खूलकर, 136504 रुपये के दिन के उच्च और 135388 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 134916 रुपये के पिछले बंद के सामने 1482 रुपये या 1.1 फीसदी की बढ़त के साथ 136398 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 214498 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 216596 रुपये के ऑल टाइम हाई और नीचे में 214498 रुपये पर पहुंचकर, 212872 रुपये के पिछले बंद के सामने 2878 रुपये या 1.35 फीसदी की तेजी के संग 215750 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 2676 रुपये या 1.25 फीसदी की तेजी के संग 216277 रुपये प्रति किलो

कमोडिटी वायदाओं में 36079.35 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 214960.4 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 28410.90 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 34290 पॉइंट के स्तर पर

हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 2747 रुपये या 1.29 फीसदी बढ़कर 216317 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

मेटल वर्ग में 4166.38 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा दिसंबर वायदा 16.65 रुपये या 1.48 फीसदी बढ़कर 1138.3 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता दिसंबर वायदा 3.45 रुपये या 1.14 फीसदी की तेजी के संग 306.2 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इसके सामने एल्यूमीनियम दिसंबर वायदा 2.3 रुपये या 0.81 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 286.8 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा दिसंबर वायदा 55 पैसे या 0.3 फीसदी के सुधार के साथ 182.35 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 3495.76 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 5230 रुपये के भाव पर खूलकर, 5255 रुपये के दिन के उच्च और 5225 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 17 रुपये या 0.33 फीसदी की बढ़त के साथ 5240 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी जनवरी वायदा 15 रुपये या 0.29 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 5240 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। इनके अलावा नैचुरल गैस दिसंबर वायदा सत्र के आरंभ में 356.4 रुपये के भाव पर खूलकर, 362 रुपये के दिन के उच्च और 354.1 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 351.2 रुपये के पिछले बंद के सामने 7.2 रुपये या 2.05 फीसदी की बढ़त के साथ 358.4 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी दिसंबर वायदा 7.8 रुपये या 2.22 फीसदी बढ़कर 358.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था। कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल दिसंबर वायदा 930 रुपये पर खूलकर, 1.2 रुपये या 0.13 फीसदी की तेजी के संग 932.5 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 16596.54 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 11814.36 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 3528.73 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 189.19 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 17.98 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 430.47 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 364.97 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 3120.04 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 17143 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 81106 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 21900 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 328634 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 36008 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 17028 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 41381 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 108078 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 21424 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 44983 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स दिसंबर वायदा 34319 पॉइंट पर खूलकर, 34351 के उच्च और 34236 के नीचले स्तर को छूकर, 381 पॉइंट बढ़कर 34290 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल जनवरी 5200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 5.9 रुपये की बढ़त के साथ 184 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस दिसंबर 360 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 50 पैसे के सुधार के साथ 3.55 रुपये हुआ।

सोना दिसंबर 139000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 510.5 रुपये की बढ़त के साथ 1340.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी दिसंबर 215000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 462 रुपये की बढ़त के साथ 2525 रुपये हुआ। तांबा दिसंबर 1130 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 7.95 रुपये की बढ़त के साथ 9.85 रुपये हुआ। जस्ता दिसंबर 310 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 50 पैसे की नरमी के साथ 0.27 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल जनवरी 5200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 12.7 रुपये की गिरावट के साथ 147.7 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस दिसंबर 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 4.2 रुपये की गिरावट के साथ 1.65 रुपये हुआ।

सोना दिसंबर 135000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 446 रुपये की गिरावट के साथ 515 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी दिसंबर 215000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 2354.5 रुपये की गिरावट के साथ 1869 रुपये हुआ। तांबा दिसंबर 1120 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 2.94 रुपये की गिरावट के साथ 0.4 रुपये हुआ। जस्ता दिसंबर 315 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 5.54 रुपये की गिरावट के साथ 9.04 रुपये हुआ।